हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

# मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 79 बेमेतरा, बुधवार 04 नवम्बर 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

# नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़ : अमित शाह

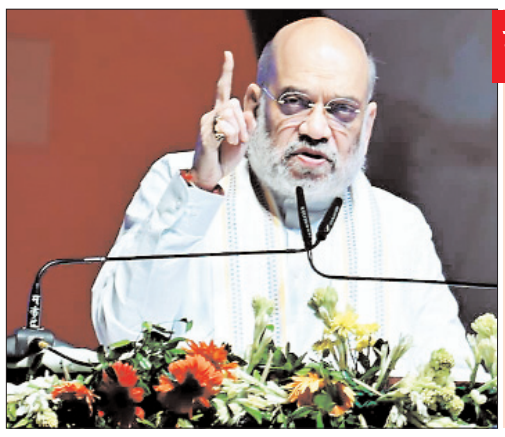

## नक्सलवाद के अवरोध दूर होने से पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं का होगा विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, खनिज संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण प्रदेश है। नक्सलवाद के कारण लंबे समय तक बस्तर सहित अनेक क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो सकीं। अब सुरक्षा और शांति का वातावरण बनने से पर्यटन, उद्योग, व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मां बम्लेश्वरी मंदिर, मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर दशहरा जैसी प्रमुख पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थलों में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी पर्यटन राज्यों में अपनी पहचान स्थापित करेगा। शाह ने कहा कि पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदेश गुरु घासीदास के सामाजिक समानता के संदेश और गुरु नानक देव जी की सेवा एवं सत्य की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करता है। सेवा, समरसता और सच्चाई छत्तीसगढ़ के सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार हैं।

**रायपुर।** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के भय और हिंसा के वातावरण से निकलकर शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता था कि यहां की धरती अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं।

आने वाले दस वर्षों में छत्तीसगढ़ की धरती भी समृद्ध रहेगी और यहां के लोग भी समृद्ध एवं खुशहाल होंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किए। उन्होंने महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त की राशि भी प्रदेश की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अपने उद्बोधन की शुरुआत भारत माता, प्रभु श्रीराम और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव, सिद्धि और संकल्प का दिन है। गौरव, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस विरासत का है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य की पहचान दी। सिद्धि नक्सलवाद के उन्मूलन के संकल्प की है और संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी की दूरदर्शिता और इस क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के पीछे यहां की जनता को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नई पहचान देने का उद्देश्य था। शाह ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को संवारने का कार्य किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों ने लंबे समय तक हिंसा और भय का सामना किया है। जिन जंगलों में महुआ, तेंदूपत्ता और लोकगीतों की पहचान होनी चाहिए थी, वहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए थीं, उन्हें हिंसा की ओर धकेला गया। स्कूलों और सड़कों जैसी विकास की बुनियादी सुविधाओं को भी नक्सली हिंसा से नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए स्पष्ट रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के पराक्रम और स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं विकास का वातावरण तैयार हुआ है। शाह ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है। जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर दिया जाता है।

## मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की सौजन्य मुलाकात



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सौजन्य मुलाकात की।

## सीआईएसएफ की नई कमान व्यवस्था में भिलाई बना स्टील सेक्टर का राष्ट्रीय मुख्यालय

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के भिलाई को देश की औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए भिलाई को स्टील सेक्टर का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया है। यहां से देशभर के इस्पात प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाएगा। सीआईएसएफ ने 1 नवंबर 2026 से पुरानी क्षेत्रीय कमान व्यवस्था के स्थान पर विशेषीकृत कार्यात्मक कमान प्रणाली लागू की है। गृह मंत्रालय की सहमति से किए गए इस पुनर्गठन में प्रतिष्ठानों की भौगोलिक स्थिति के बजाय उनकी प्रकृति और कार्यक्षेत्र के आधार पर कमान निर्धारित की गई है। इसके तहत पावर-1 (नई दिल्ली), पावर-2 (कोलकाता), कोयला (रांची), स्टील (भिलाई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (गुवाहाटी), पश्चिमी तट बंदरगाह (मुंबई), पूर्वी तट बंदरगाह (चेन्नई) तथा जीबीएमएम एवं एमआरटीएस (नई दिल्ली) सेक्टर गठित किए गए हैं।

## पीएम मोदी बोले- ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा का आधार



**नई दिल्ली।** वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10-11 साल में 500 गीगावाट अतिरिक्त रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा ही आर्थिक सुरक्षा का आधार है. भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपनी विकास दर बनाए रखने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दुनिया ने कोरोना महामारी से लेकर पश्चिम एशिया संकट तक कई बड़े आर्थिक झटकों का सामना किया है. पश्चिम एशिया का संकट तो अभी भी जारी है लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को इस गर्व है कि हमने अब तक इस संकट को बेहतर तरीके से संभाला है. साथ ही भारत की ग्रोथ ऊंची बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर देश ने पिछले 10 साल में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश नहीं किया होता, नई व्यवस्थाएं नहीं बनाई होतीं तो देश में ऊर्जा संकट दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी ज्यादा गंभीर हो सकता था. ऊर्जा सुरक्षा ही असल में आर्थिक सुरक्षा का आधार है. इस दौरान उन्होंने देश की उपलब्धियों का ब्योरा भी दिया।

पीएम मोदी ने बताया कि भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित है. पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन देश ने इसे समय से 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा कर लिया. फिलहाल भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 300 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है. 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हर हाल में हासिल किया जाएगा।

## सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों से भारतीय नौसेना ने छुड़ाया जहाज, चालक दल सुरक्षित



**नयी दिल्ली।** भारतीय नौसेना ने सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाले जहाज 'अजिनी' को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया। नौसेना के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 48 घंटे से अधिक चले अभियान में जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस कार्रवाई में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। नौसेना के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने जहाज का अपहरण कर लिया था। आशंका थी कि लुटेरे इसका इस्तेमाल दूसरे व्यापारिक जहाजों पर हमले के लिए कर सकते हैं। सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने एक युद्धपोत और समुद्री निगरानी विमान को अभियान में लगाया। लगातार निगरानी के बाद जहाज का पता लगाया गया और उसकी आवाजाही रोकने के लिए कदम उठाए गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के सी-17 विमान से मरीन कमांडो को सटीक तरीके से उतारा गया।

नौसेना के कमांडो ने कार्रवाई कर जहाज को अपने नियंत्रण में लिया और समुद्री लुटेरों के खतरे को खत्म करते हुए सभी 20 लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया।

## युद्ध की बदलती चुनौतियों के लिए सेना को नई प्रौद्योगिकी और ताकत से लैस करने की तैयारी : राजनाथ

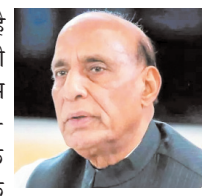

**नयी दिल्ली।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना को मौजूदा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार सक्षम बनाना जरूरी है इसलिए युद्ध के बदलते तौर-तरीकों को देखते हुए उसे आधुनिक प्रौद्योगिकी, नए हथियारों और बेहतर युद्धक क्षमता से लैस करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ-साथ ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने मंगलवार को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, बदलती युद्ध परिस्थितियों और भविष्य की सैन्य जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें आधुनिक हथियारों और सैन्य प्रणालियों को सेना में शामिल करने, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त योजना और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सेना को नई प्रौद्योगिकियों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित किए जा रहे आधुनिक हथियारों, मिसाइलों और सैन्य प्रणालियों का जिक्र किया। साथ ही रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों, छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही।

## रेवंत ने 'खेलो इंडिया गेम्स' के लिए विश्वस्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करने का दिया निर्देश



**हैदराबाद।** तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को 11 से 22 दिसंबर तक राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया युवा खेलों के आठवें संस्करण के लिए स्थायी और उच्च गुणवत्ता वाली व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन के लिए तैयार किया जाने वाला बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए, जिसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम एमसीआरएचआरडी संस्थान में आयोजित एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि 'खेलो इंडिया गेम्स' की तैयारियों को 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' के साथ जोड़कर किया जाए, ताकि सम्मेलन के लिए विकसित किए गए संसाधनों का इस्तेमाल खेल आयोजन में भी किया जा सके।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन खेलों के जरिए युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में वे ओलंपिक पदक जीत सकें। उन्होंने युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए स्थायी खेल बुनियादी ढांचा तैयार करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि ग्रुप-1 अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए और प्रशिक्षु अधिकारियों तथा जिला-स्तरीय अधिकारियों को संबंधित स्थानों पर व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए कहा जाए। रेड्डी ने हर सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पिछली सरकार के दौरान खेल आयोजनों में जो कमियां देखी गई थीं, उनकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने मौजूदा अल नीनो के मद्देनजर सुझाव दिया कि उद्घाटन और समापन समारोहों को बिना किसी अनावश्यक खर्च के सरल रखा जाए। इन खेलों में 7,000 से अधिक खिलाड़ियों और लगभग 2,000 प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें 27 खेल विधाएं और एक प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल होगा, जो छह शहरों के 20 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तेलंगाना की पारंपरिक मार्शल आर्ट, 'करसामु' को मेजबान राज्य के कोटे में शामिल करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।कल रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बैठक में मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव और वकिती श्रीहरी, खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी, मुख्य सचिव संजय जाजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

## बस्तर के जनजातीय टिन संग्राहकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए विकसित TIN पोर्टल की केंद्रीय मंत्री ने की विशेष प्रशंसा

# खनिज संपदा का समुचित उपयोग कर छत्तीसगढ़ को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाएंगे : सीएम साय




**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रदेश के खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर खनिज संसाधनों का समुचित, वैज्ञानिक और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि खनिज संपदा का लाभ केवल औद्योगिक विकास तक सीमित न रहे, बल्कि इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों, विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों तक पहुंचे। खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, निवेश, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय अपने निवास कार्यालय रायपुर में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में आयोजित खनन एवं कोयला क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, कोयला उत्पादन, क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों के विकास, जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि के उपयोग तथा खनन गतिविधियों में आधुनिक तकनीक के समावेश सहित विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम है। देश की बढ़ती औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप खनिज संसाधनों का अन्वेषण और उपयोग किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों और प्रभावित समुदायों के हितों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब खनिज संपदा से प्राप्त आर्थिक लाभ प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खनिज प्रशासन में पारदर्शिता, तकनीक के अधिकतम उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। खनिज ऑनलाइन 2.0, डिजिटल निगरानी व्यवस्था और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खनन गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के जनजातीय समुदायों को टिन अयस्क का बेहतर मूल्य दिलाने और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए TIN पोर्टल जैसी पहल प्रारंभ की गई है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश की खनिज संपदा स्थानीय समुदायों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका के नए अवसरों का आधार बने। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों, राजस्व वृद्धि और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और वे देश में जहां भी जाते हैं, राज्य सरकार के अच्छे कार्यों और प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। विशेष रूप से खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल, ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग, खनन गतिविधियों की स्टार रेटिंग और डिजिटल निगरानी व्यवस्था की उन्होंने प्रशंसा की।

# सेंसेक्स करीब एक हजार अंक उछला

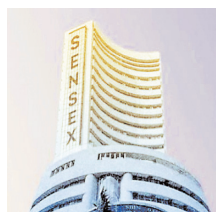


**मुंबई।** घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को भी तेजी जारी रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दोपहर तक करीब एक हजार अंक उछल गया। सेंसेक्स सुबह 596 अंक की बढ़त में 76,288.65 अंक पर खुला। धीरे-धीरे इसका ग्राफ और ऊपर चढ़ता गया। दोपहर के समय यह 984 अंक की बढ़त बनाते हुए 76,676.58 अंक पर पहुंच गया था। खबर लिखे जाते समय यह 817.36 अंक (1.08 फीसदी) चढ़कर 76,510.14 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 141 अंक ऊपर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 224.20 अंक यानी 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,665 अंक पर था। वृहत बाजार में सभी सूचकांक हरे निशान में हैं। सेक्टर आधारित सूचकांकों में एफएमसीजी, वित्त, बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी और रसायन समूहों में अधिक लिवाली रही। फार्मा, धातु, आईटी और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांकों में गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स का शेयर साढ़े तीन प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक का तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी में है।

# नक्सलमुक्त बीजापुर में पहली बार राज्योत्सव का आयोजन, शांति के बाद अब विकास की बारी : मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

## मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय आयोजन, अंदरूनी गांवों तक सड़क, बिजली और शिक्षा सुविधाएं पहुंचाने पर जोर







मूक पत्रिका

**बीजापुर/आशीष पदमवार।** नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकलकर विकास की राह पर आगे बढ़ रहे बीजापुर में पहली बार राज्योत्सव का आयोजन हुआ। बीते सोमवार को जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा और विश्वास का नया वातावरण बना है। अब इस माहौल में अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास की सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।मंत्री साहेब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। इसमें सुरक्षा बलों के जवानों का साहस, समर्पण और बलिदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जवानों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि बेहतर सुरक्षा वातावरण बनने से दूरस्थ गांवों में विकास कार्यों की संभावनाएं बढ़ी हैं।उन्होंने कहा कि जिले में सड़क, बिजली, पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लंबे समय से बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने से स्थानीय बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में लिए गए फैसलों से जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

### अंदरूनी गांवों तक सुविधाएं पहुंचाने की चुनौती

मंत्री ने कहा कि बीजापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और आजीविका के क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ दूरस्थ गांवों में रहने वाले पात्र परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने जिलेवासियों से शांति, सद्भाव और विकास की प्रक्रिया में भागीदारी निभाने की अपील की। समारोह में कलेक्टर विश्वदीप ने जिले की विकास यात्रा और योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा वातावरण में अंदरूनी गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकता विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

### प्रदर्शनी में दिखाई विभागीय योजनाओं की झलक

राज्योत्सव में विभिन्न विभागों की ओर से विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ली। प्रदर्शनी में कृषि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना से जुड़ी गतिविधियां प्रदर्शित की गई।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, उपाध्यक्ष पेरे पुलैय्या, पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता, वनमंडलाधिकारी डॉ. जाधव सागर, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में जिलेवासी उपस्थित रहे।

### राज्योत्सव में दोहराया विकसित बीजापुर का संकल्प

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने जिलेवासियों से शांति, सद्भाव और विकास की यात्रा में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंदरूनी गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के साथ रोजगार, पर्यटन और आजीविका के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। समारोह में 'शांति का बीजापुर, समृद्धि का बीजापुर और विकसित बीजापुर' बनाने का संकल्प दोहराया गया।

# अमित बघेल के हाथों देवकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिहोरे का अनशन समाप्त; जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में हुए शामिल



मूक पत्रिका

**बेमेतरा / देवकर** -देवकर नगर पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सिहोरे पिछले सात दिनों से सीएमओ की तानाशाही और मनमानी कार्यशैली के खिलाफअनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। लगातार सात दिनों से चले आ रहे इस विरोध प्रदर्शन का आखिरकार समापन हो गया।जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित बघेल ने अनशन स्थल पर पहुंचकर सुरेश सिहोरे को जल पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही, स्थानीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। देवकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने पारंपरिक राजनीतिक दलों–भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस–का हाथ छोड़कर क्षेत्रीय स्वाभिमान की प्रतीक 'जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी' की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अमित बघेल की उपस्थिति में पार्टी का गमछा धारण कर छत्तीसगढ़िया हितों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर बोलते हुए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित बघेल ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी लगातार जनप्रतिनिधियों और आम जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सुरेश सिहोरे का यह कदम छत्तीसगढ़िया सम्मान और हक की लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा।इस दौरान जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

# ऑनलाइन सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, पुलिस ने किया अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश



मूक पत्रिका

**जांजगीर-चांपा।** ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्वष्ठत्र (बिग डैडी गेम) ऑनलाइन सट्टा ऐप के अंतरराज्यीय नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किरण महादु साल्वे, निवासी दत्ता नगर, थाना दौंड, जिला पुणे (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांजगीर लाने के बाद न्यायालय में पेश किया है। उसके बैंक खाते में जमा राशि को भी फ्रीज कराया गया है। पुलिस के अनुसार साइबर थाना जांजगीर को सूचना मिली थी कि न्यू चंदनियापारा लिंक रोड निवासी हेमलाल यादव मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई कर उसे पकड़ा। पूछताछ में हेमलाल ने क्वष्ठत्र ऑनलाइन सट्टा गेम खेलने और इसके बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी दी। उसने बताया कि उसे सट्टा खेलने की आईडी शैलेंद्र कुमार शर्मा उपलब्ध कराता था।इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर शैलेंद्र कुमार शर्मा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र बीडीजी ऐप की मास्टर आईडी और लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाता था। यह नेटवर्क कमीशन आधारित तरीके से संचालित होता था। नए लोगों को जोड़ने और उनके द्वारा सट्टे में रकम लगाने पर नेटवर्क से जुड़े ऊपर के संचालकों को कमीशन मिलता था। इस मामले में पूर्व में छह आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।पुलिस की पूछताछ में शैलेंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र निवासी किरण साल्वे ने टेलीग्राम पर 'ईगल क्वष्ठत्र गेम' नाम से चैनल बनाया था। इसी चैनल के माध्यम से शैलेंद्र को जांजगीर जिले में नेटवर्क का एडमिन बनाया गया था। पुलिस के अनुसार सट्टे में रकम जमा कराने और कमीशन के लेनदेन की व्यवस्था भी इसी नेटवर्क के जरिए संचालित होती थी।टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैटिंग तथा वित्तीय लेनदेन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने किरण साल्वे की भूमिका सामने आने पर उसे पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क के दूसरे राज्य तक फैले कनेक्शन का खुलासा हुआ है।पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क पारंपरिक जुए से अलग हाईटेक तरीके से संचालित हो रहा था। इसमें मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और स्ष्ठञ्ज (क्रिप्टो डिजिटल करेंसी) के माध्यम से वित्तीय लेनदेन किए जाने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं भारतीय न्याय संहिता (क्वहृस्) की धारा 112(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

# सेजेस बडेराजपुर खेल मैदान में दो दिवसीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन, 32 खेल विधाओं को मिलेगा बढ़ावा





मूक पत्रिका

**कोंडागांव।** जिला कोंडागाँव के विकासखंड बडेराजपुर में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बडेराजपुर के तत्वावधान में बस्तर ओलंपिक 2026 का आयोजन 2 से 3 नवंबर तक सेजेस बडेराजपुर के खेल मैदान में किया जा रहा है।प्रतियोगिता में एथलेटिक्स (100, 200 एवं 400 मीटर दौड़, रिले रेस), गोला फेंक, तवा फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, बैडमिंटन (एकल एवं युगल), कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल एवं फुटबॉल सहित विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिताएं जूनियर बालक-बालिका एवं सीनियर महिला-पुरुष वर्ग में आयोजित की जा रही हैं।

बडेराजपुर संकुल प्राचार्य सी.एल. मरकाम ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी 4 एवं 5 नवंबर को मारंगपुरी में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों की छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना तथा युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना का विकास करना है। बस्तर ओलंपिक के माध्यम से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

# राज्योत्सव में श्री सुनील मानिकपुरी, स्कूली छात्र–छात्राओं ने दी प्रस्तुति





मूक पत्रिका

**जांजगीर-चांपा।** छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवंबर को शासकीय हाई स्कूल मैदान, जांजगीर में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध गायक श्री सुनील मानिकपुरी ने अपनी रंगारंग सांगीतिक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली छात्र-छात्राओं ने प्रदेश की गौरवशाली लोक परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विविध कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। जिला स्तरीय राज्योत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, नवाचारों एवं उपलब्धियों पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे। विभागीय प्रदर्शनी में शासन की योजनाओं और जिले में किए जा रहे विकास कार्यों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया, जो राज्योत्सव में आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लगाई गई स्टॉल में विकसित भारत जी राम जी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिहान एवं स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों को आकर्षक मॉडल एवं प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। राज्योत्सव के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक एवं जनप्रतिनिधियों ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी ली तथा विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

## पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो परिजनों के साथ धरने पर बैठेंगे - विक्रम लहरे

# दीपा सागर की संदिग्ध मौत पर उठे गंभीर सवाल! दुकान मालिक की जवाबदेही तय हो



मूक पत्रिका

**जगदलपुर।** शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाफ्ना हाउस में युवती दीपा सागर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतिका दीपा सागर जगदलपुर के मां दंतेश्वरी वार्ड क्रमांक 20 की निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित थी। युवती बाफ्ना लाइफस्टाइल कपड़ा शोरूम में काम कर रही थी। उसका शव फांसी पर लटका हुआ मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

परिजनों द्वारा युवती के शरीर पर चोट एवं नाखून के निशान होने का दावा किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में देरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में यह मामला केवल एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और संस्थान की जवाबदेही का भी गंभीर विषय है।

इस मामले में विनीत विक्रम लहरे, जिलाध्यक्ष सर्व अनुसूचित जाति समाज, जिला बस्तर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी दुकान, शोरूम या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

दुकान मालिक एवं प्रबंधन की जवाबदेही तय हो विक्रम लहरे ने कहा कि जब कोई कर्मचारी किसी दुकान, शोरूम या प्रतिष्ठान में काम करता है, तो उसके कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मालिक एवं प्रबंधन की होती है। यदि किसी कर्मचारी के साथ काम के दौरान अथवा कार्यस्थल से संबंधित परिसर में कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना होती है, तो उसकी परिस्थितियों और लागू श्रम कानूनों के अनुसार मालिक एवं प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए।

दीपा सागर की मौत बाफ्ना हाउस में हुई है। ऐसे में बाफ्ना लाइफस्टाइल शोरूम के मालिक एवं प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस घटना में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में सुरक्षा संबंधी लापरवाही या कानूनी जिम्मेदारी सामने आती है, तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए।

### हमारी प्रमुख मांगें

1.दीपा सागर की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

2.बाफ्ना हाउस एवं बाफ्ना लाइफस्टाइल शोरूम के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर उनकी जांच की जाए।

3.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर बताए गए चोट एवं नाखून के निशानों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

4.घटना के समय मौजूद लोगों एवं संबंधित प्रबंधन से पूछताछ की जाए।

5.शोरूम मालिक एवं प्रबंधन की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही की जांच की जाए। मृतिका के परिजनों को बाफ्ना लाइफस्टाइल शोरूम के मालिक एवं प्रबंधन से उचित आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए शासन-प्रशासन द्वारा भी पीड़ित अनुसूचित जाति परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाया जाए यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।न्याय नहीं मिला तो परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे विक्रम लहरे ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि दीपा सागर अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी थी। उसके परिवार को न्याय दिलाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करता, दोषियों की जवाबदेही तय नहीं होती अथवा पीड़ित परिवार को न्याय एवं उचित मुआवजा दिलाने में लापरवाही बरती जाती है, तो सर्व अनुसूचित जाति समाज पीड़ित परिवार के साथ जिला प्रशासन के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को प्रभाव और पैसे के दम पर जांच से बचने नहीं दिया जाना चाहिए गरीब परिवार की बेटी की मौत को सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज करना उचित नहीं है

हमारी मांग स्पष्ट है–दीपा सागर की मौत की सच्चाई सामने आए, कार्यस्थल की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी तय हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार कठोर सजा मिले। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

# दल्ली राजहरा के गौ सेवक अमर लालवानी का छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में भव्य सम्मान



मूक पत्रिका

दल्ली राजहरा- हमारे शहर एवं आसपास क्षेत्र के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि दल्ली राजहरा के सभी गौ सेवक, जो निस्वार्थ भाव से तन, मन और धन से निःशुल्क गौ सेवा में समर्पित हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर सम्मानित किया गया। कल आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग, बालोद जिला कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, बालोद नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी एवं दल्ली राजहरा नगर पालिका अध्यक्ष तोरण साहू के करकमलों द्वारा गौ सेवकों को सम्मान प्रदान किया गया।

इस सम्मान समारोह में गौ सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे सभी सेवकों की सेवाभावना की सराहना की गई। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि निःस्वार्थ गौ सेवा समाज के लिए प्रेरणादायी है। गौ भक्त अमर लालवानी एवं उनकी पूरी टीम को यह सम्मान प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

# बेमेतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

**10.69 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, 535 पौवा अंग्रेजी शराब बरामद; ईको कार, स्कॉर्पियो और एक्टिवा से हो रही थी शराब की सप्लाई**

मूक पत्रिका



**बेमेतरा -** जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बेमेतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में साइबर सेल, थाना नांदघाट एवं थाना चंदनू की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 535 पौवा अंग्रेजी शराब (96,300 एमएल), शराब परिवहन में प्रयुक्त ईको कार, स्कॉर्पियो वाहन, एक सोल्ड एक्टिवा और तीन मोबाइल फोन सहित कुल 10 लाख 69 हजार 200 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।पुलिस के अनुसार, 30 अक्टूबर को थाना चंदनू पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम उसलापुर में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी दिलीप बंजारे (26 वर्ष), निवासी उसलापुर को 82 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि शराब उसे बेमेतरा निवासी राजू साहू द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई थी।इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए राजू साहू (26 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अवैध शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आई। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त ईको कार क्रमांक छत्त 04 चह्व 4801 और मोबाइल फोन भी जब्त किया।इसी क्रम में 31 अक्टूबर को थाना नांदघाट पुलिस को ग्राम नयापारा करमसेन निवासी मोतीलाल साहू के घर में अवैध शराब संग्रहित होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोतीलाल साहू (27 वर्ष) को 453 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में डोमन निषाद उर्फ हर्ष निषाद (19 वर्ष) तथा बिलासपुर निवासी मनोज यादव (32 वर्ष) के साथ मिलकर शराब खरीदने और सप्लाई करने की बात सामने आई।प्रकरण में पुलिस ने डोमन निषाद उर्फ हर्ष निषाद के कब्जे से शराब सप्लाई में प्रयुक्त सोल्ड एक्टिवा जब्त की। वहीं, आगे की विवेचना एवं पूछताछ के आधार पर 02 नवंबर को बिलासपुर निवासी मनोज यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक छत्त 10 क्वह्व 4324 तथा दो मोबाइल फोन जब्त किए गए।

**जांच में सामने आई नकली शराब की आशंका**-पुलिस जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। जब्त की गई शराब की बोतलों में शासन का होलोग्राम नहीं लगा पाया गया। वहीं, शराब की शीशियों पर चिपकाए गए रेपर भी कूटरचित पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इस तरह शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला भी सामने आया है। जांच के दौरान प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 36 तथा भारतीय न्याय संहिता (क्वह्वस्) की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान शराब की सप्लाई किन-किन लोगों तक की जा रही थी, इसकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी मनोज यादव द्वारा राजा भाठिया से संपर्क कर शराब प्राप्त करने की बात बताई गई है। पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है।

**10.69 लाख रुपये की संपत्ति जब्त**-पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति में शराब सप्लाई में प्रयुक्त ईको कार (6 लाख रुपये), स्कॉर्पियो वाहन (2.50 लाख रुपये), तीन मोबाइल फोन (75 हजार रुपये), सोल्ड एक्टिवा (80 हजार रुपये) तथा 535 पौवा अंग्रेजी शराब (64 हजार 200 रुपये) शामिल हैं। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 69 हजार 200 रुपये बताई गई है। इस संयुक्त कार्रवाई में प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी नांदघाट निरीक्षक लेखराम ठाकुर, थाना चंदनू से निरीक्षक सुरेन्द्र मानिकपुरी सहित साइबर सेल, थाना नांदघाट एवं थाना चंदनू के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

# ओबीसी महासभा ने बस्तर में युवा संगठन को दी नई जिम्मेदारी, मनोज कुमार ठाकुर बने जिला अध्यक्ष







**देवनाथ ठाकुर को जिला उपाध्यक्ष और सदासिंह ठाकुर को बस्तर संभाग सचिव की जिम्मेदारी**

मूक पत्रिका

जगदलपुर। ओबीसी महासभा ने संगठनात्मक मजबूती और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में बस्तर जिले में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। संगठन की ओर से मनोज कुमार ठाकुर को ओबीसी महासभा युवा प्रकोष्ठ बस्तर जिला अध्यक्ष, देवनाथ ठाकुर को जिला उपाध्यक्ष तथा सदासिंह ठाकुर को बस्तर संभाग सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इन नियुक्तियों के माध्यम से संगठन ने बस्तर संभाग में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने की पहल की है। ओबीसी महासभा का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर जोड़ना, सामाजिक एकता एवं आपसी समन्वय को बढ़ावा देना तथा समाज से जुड़े मुद्दों को संगठित रूप से उठाना है।नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, युवाओं को जोड़ने और समाज के लोगों के बीच संवाद एवं जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। संगठनात्मक विस्तार के साथ ही सामाजिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व और समाज के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।

ओबीसी महासभा में युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी मिलने से बस्तर जिले में संगठन की गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभचिंतकों एवं समाज के लोगों ने बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं।

# छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर श्री राम सेवा समिति चोरिया ने चलाया स्वच्छता अभियान

मूक पत्रिका



**जांजगीर-चांपा।** छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर श्री राम सेवा समिति चोरिया द्वारा गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। अभियान में समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गांव के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई की।इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अखिल साहू, उपाध्यक्ष लोकेश देवांगन, सचिव क्रांति कुमार देवांगन एवं कोषाध्यक्ष ध्रुव कुमार साहू सहित सक्रिय सदस्य उत्तराकांत कश्यप, दीनदयाल देवांगन, दुलेश्वर साहू, लोचन कहरा, डॉक्टर फ्रित साहू, डॉक्टर संतोष देवांगन, भागीरथी बरेठ, विजय साहू एवं उत्तम देवांगन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी श्रमदान कर अपनी सहभागिता निभाई।

समिति की इस पहल की ग्रामवासियों ने सराहना करते हुए इसे गांव के विकास और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में सराहनीय कदम बताया। समिति के सदस्यों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आयोजित यह अभियान सामाजिक एकता, जनसेवा और सामूहिक सहभागिता की मिसाल बना।

# राज्योत्सव में जीजीवी के म्यूजिक बैंड 'तरंग' की धूम, अंशुल तिवारी की गायकी ने बांधा समां

**उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक सुशांत शुक्ला ने की युवा कलाकारों की प्रतिभा की सराहना, हजारों श्रोता हुए मंत्रमुग्ध**

मूक पत्रिका



**जांजगीर-चांपा।** छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (जीजीवी) के आधिकारिक म्यूजिक बैंड 'तरंग' ने अपनी शानदार संगीतमय प्रस्तुति से हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बैंड के कलाकारों ने गायन और वादन की मनमोहक प्रस्तुति देकर पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अंशुल तिवारी की शानदार गायकी रही। उनकी सधी हुई आवाज और ऊर्जावान प्रस्तुति पर दर्शक झूम उठे। इसके बाद अंशुल तिवारी और शिवम की जोड़ी ने सुरों की शानदार जुगलबंदी पेश कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में 'तरंग' बैंड की पूरी टीम ने सामूहिक गीत की भव्य प्रस्तुति दी। इसमें सौम्य, आदर्श, वैभव, अभय, हर्ष भोसले, नयना, पंकज, गौरहरि, आशीष वैष्णव, शिवम, अंशुल, नयन, देबिका और लव्या ने अपने गायन एवं वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं की कला और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के मंच मिलना गौरव की बात है।

विधायक सुशांत शुक्ला ने भी सभी कलाकारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अतिथियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं 'तरंग' बैंड के सभी सदस्यों को शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई दी।राज्योत्सव के मंच पर 'तरंग' बैंड की इस प्रस्तुति ने युवा प्रतिभाओं की रचनात्मक क्षमता और संगीत के प्रति उनके समर्पण को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया।

# स्विगी ने इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर डिलीवरी पार्टनर्स के लिए व्यापक बीमा योजना को आगे बढ़ाया

**रायपुर।** भारत के प्रमुख ऑन-डिमांड सुविधा प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy Ltd, NSE: SWIGGY / BSE: 544285) ने आज इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए व्यापक बीमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की घोषणा की। इस पहल के जरिए दोनों कंपनियों ने देश में तेजी से बढ़ रहे गिग वर्कफोर्स की आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त वर्ष 2026 में स्विगी के दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के तहत 25 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।

इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस के साथ नवीनीकृत बीमा योजना के तहत डिलीवरी पार्टनर्स को पहले की तरह 10,00,000रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर, अस्पताल में भर्ती होने पर 2,00,000रुपये तक का बीमा कवर और परिवार के लिए 1,00,000रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता रहेगा।इसके अलावा, सभी महिला डिलीवरी पार्टनर्स और उन पुरुष डिलीवरी पार्टनर्स की पत्नियों को भी मातृत्व लाभ दिया जाएगा, जिनकी बीमा योजना में परिवार का कवर शामिल है। पिछली बीमा अवधि के दौरान मातृत्व संबंधी कुल दावों में से 75 प्रतिशत का लाभ डिलीवरी पार्टनर्स की पत्नियों ने उठाया, जबकि शेष 25 प्रतिशत लाभ स्विगी की महिला डिलीवरी

# हिंदवेयर ने रायपुर में दो नए गैलेरिया ब्रांड स्टोर के साथ छत्तीसगढ़ में उपस्थिति सुदृढ़ की




**रायपुर।** हिंदवेयर, भारत का अग्रणी बाथवेयर ब्रांड, ने रायपुर में दो नए विशेष गैलेरिया ब्रांड स्टोर के उद्घाटन के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी रिटेल उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है। पाचपेड़ी नाका के प्रमुख स्थान पर स्थित ये दोनों स्टोर, वीएमजी एंटरप्राइजेज और गुप्ता ट्रेडर्स द्वारा संचालित हैं। अनुभव-आधारित रिटेल स्पेस (वास्तविक अनुभव प्रदान करने वाला रिटेल स्थान) के रूप में डिज़ाइन किए गए ये नए ब्रांड स्टोर हिंदवेयर की सैनिटरीवेयर, नल, शावर और बाथरूम समाधानों की उत्पाद श्रृंखला को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे उपभोक्ता, वास्तुकार और इंटीरियर डिज़ाइनर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिज़ाइन, फ़िनिशिंग और कार्यक्षमता को देख-परख सकते हैं। स्टोर शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए, श्री निरुपम सहाय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदवेयर, ने कहा, रायपुर मध्य भारत में एक प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ आवासीय विकास, सुधरते बुनियादी ढाँचे और नया रायपुर सहित आसपास के क्षेत्र के विस्तार होम इंप्रूवमेंट सेक्टर के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता अपने घरों में अधिक निवेश कर रहे हैं, हम ऐसे उत्पादों में भी अधिक रुचि देख रहे हैं जो डिज़ाइन, कार्यक्षमता और गुणवत्ता का संगम हों। हमारे गैलेरिया ब्रांड स्टोर बाज़ार में हमारी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और उपभोक्ताओं, वास्तुकारों तथा डिज़ाइनरों को हिंदवेयर की संपूर्ण बाथरूम उत्पाद श्रृंखला को देखने-परखने और अपनी आवश्यकताओं व रुचियों के अनुरूप स्थान सँवारने के लिए एक समर्पित स्थान उपलब्ध कराते हैं। छत्तीसगढ़ में हमें अपार संभावनाएँ दिखती हैं और हम पूरे राज्य में अपनी रिटेल उपस्थिति का विस्तार करते रहेंगे।

# स्कोडा ऑटो इंडिया ने 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों का आंकड़ा पार किया, 193 शहरों तक पहुँच का विस्तार किया

**रायपुर।** स्कोडा ऑटो इंडिया ने देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 193 शहरों में 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे ग्राहकों के लिए इसके उत्पादों और वाहन स्वामित्व संबंधी सेवाओं तक पहुँच और आसान हुई है। 30 अक्टूबर, 2026 को इम्फाल में अपने 350वें ग्राहक संपर्क केंद्र का उद्घाटन करके ब्रांड ने यह उपलब्धि हासिल की और इसके साथ ही मणिपुर में भी प्रवेश किया। यह विस्तार स्थापित बाजारों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों में भी बिक्री और बिक्री-पश्चात सेवाओं को ग्राहकों के और करीब पहुँचाने की स्कोडा ऑटो इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा, 193 शहरों में 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों का




आंकड़ा पार करना पूरे भारत में ग्राहकों के लिए स्कोडा को और करीब लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे मौजूदा और नए डीलर साझेदार इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा हैं। भारत में स्कोडा ब्रांड को और मजबूत बनाने के हमारे दृष्टिकोण को साझा करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नए बाजारों में प्रवेश करते समय हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है— बिक्री और बिक्री-पश्चात सेवाओं के दौरान ग्राहकों को एक समान और समृद्ध अनुभव प्रदान करना। हमारे बढ़ते उत्पाद पोर्टफोलियो और ग्राहक-केंद्रित पहलों के साथ, यह विस्तृत होता नेटवर्क ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने और देशभर में उनकी पसंद का ब्रांड बने रहने में हमारी मदद करेगा। पहुँच का विस्तार, उपस्थिति को मजबूती - स्कोडा ऑटो इंडिया का नेटवर्क 2021 में 191 ग्राहक संपर्क केंद्रों से बढ़कर 2025 में 325 और अक्टूबर 2026 तक 350 से अधिक हो गया है।

**चारों विकासखंडों में आयोजित हुए शिविर, 150 पालक-अभिभावकों और शिक्षकों ने भी लिया हिस्सा**

# विशेष आवश्यकता वाले 161 बच्चों का आकलन, योजनाओं से जोड़ने की पहल

मूक पत्रिका






**बीजापुर/आशीष पदमवार।** जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों की पहचान करने और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चारों विकासखंडों में आकलन सह शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 161 बच्चों का आकलन किया गया। वहीं 150 पालक-अभिभावकों और शिक्षकों ने सहभागिता निभाई। शिविरों के माध्यम से बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड और आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर विश्वदीप के आदेश और जिला मिशन संचालक नम्रता चौबे के निर्देशन में शिविरों का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पाण्डेय के मार्गदर्शन तथा जिला मिशन समन्वयक जी.बी.एस. रेड्डी के नेतृत्व में चारों विकासखंडों में यह गतिविधि संचालित की गई। शिविरों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन किया गया। साथ ही बच्चों और उनके पालक-अभिभावकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया समझाई गई। जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण प्राप्त करने और शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने की जानकारी भी दी गई।

**शिक्षकों और पालकों ने निभाई जिम्मेदारी**-शिविरों में शिक्षकों ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहयोग किया। वहीं पालक-अभिभावकों ने भी बच्चों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला मिशन समन्वयक जी.बी.एस. रेड्डी ने शिविरों के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले बीआरपी, शिक्षकों और पालक-अभिभावकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे भी समन्वित प्रयास जारी रहेंगे।

**आयोजन में इनकी रही भूमिका:** भोपालपटनम में बीआरपी अनिरुद्ध गिलहरे, आवापल्ली में बेदराम निषाद, बीजापुर में चितूराम बघेल और भैरमगढ़ में सुनील तायवाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक कार्यक्रम समन्वयक तारकेश्वर पैकरा का विशेष सहयोग रहा।

**बीजापुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा 68 बच्चे पहुंचे**-जिले के चारों विकासखंडों में आयोजित आकलन सह शिविर में कुल 161 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने हिस्सा लिया। इनमें बीजापुर विकासखंड से सबसे अधिक 68 बच्चे शामिल हुए। भोपालपटनम से 49, भैरमगढ़ से 24 और आवापल्ली से 20 बच्चे पहुंचे। शिविर में 150 पालक-अभिभावकों एवं शिक्षकों ने भी सहभागिता निभाई। इस दौरान बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

# संपादकीय

## जलवायु परिवर्तन और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

धरती का लगातार बढ़ता तापमान, मौसम के चक्र में अनिश्चितता और प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन में तेजी से आ रही गिरावट आज संपूर्ण मानव जाति और जीव-जगत के सामने अब तक का सबसे विकट और अस्तित्वगत संकट बनकर खड़ी हो गई है। वर्ष 2026 की भीषण गर्मियों में दुनिया के कोने-कोने में जिस प्रकार अत्यधिक तापमान, बेमौसम बारिश, बाढ़, भूस्खलन और भीषण सूखे का सामना करना पड़ा है, उसने यह स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और प्राकृतिक नियमों की अनदेखी अब और अधिक सहन करने योग्य नहीं रह गई है। मानव जाति ने विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब उसका दुष्परिणाम भीषण प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ रहा है। भारत जैसे विशाल आबादी और विविध भू-भाग वाले देश के लिए यह पर्यावरणीय संकट और भी अधिक संवेदनशील और गंभीर चिंता का विषय है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मौसम की थोड़ी सी भी अनिश्चितता सीधे तौर पर देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जल संरक्षण, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, भूजल स्तर को उठाना और प्लास्टिक व अन्य अजैव-निम्नीकरणीय कचरे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी नीतियां अब केवल सरकारी सम्मेलनों या कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रह सकतीं। इन्हें तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर धरातल पर उतारना होगा और इसके लिए कठोर विधायी कदम उठाने होंगे। सौभाग्य से, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य हुआ है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु मंचों पर भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं और निर्धारित लक्ष्यों ने यह दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा राष्ट्रीय संकल्प कितना दृढ और स्पष्ट है। आम नागरिकों के स्तर पर भी अब यह समझ धीरे-धीरे विकसित होने लगी है कि पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाना केवल एक पसंद नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए समय की सबसे बड़ी मांग है। सड़कों पर बिजली से चलने वाले वाहनों का बढ़ता उपयोग, आवासीय भवनों और कार्यालयों की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार और वर्षा जल संचय जैसी पद्धतियां अब जन-आंदोलन का रूप लेने लगी हैं। परंतु, इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है, क्योंकि समस्या का आकार बहुत बड़ा है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की अंधी दौड़ में पर्यावरण के स्थापित मानकों की अनदेखी करने वाले कारखानों और निर्माण कंपनियों के खिलाफ और अधिक सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और बिना किसी दबाव के उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश की पवित्र नदियों को औद्योगिक रसायनों और सीवर के कचरे से मुक्त करना, बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना और घटते वन क्षेत्र को बढ़ाना ऐसी प्राथमिकताएं हैं।

# स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और ग्रामीण भारत की जमीनी वास्तविकता

**मीनाक्षी सुंदरम**

किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास, सामाजिक कल्याण और प्रगति का वास्तविक पैमाना केवल उसकी आर्थिक विकास दर, औद्योगिक उत्पादन या बड़े शहरों में खड़ी ऊंची इमारतें नहीं होतीं, बल्कि यह इस बात से तय होता है कि उस देश के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं कितनी सहजता से पहुंच रही हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ नागरिक ही परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सकता है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य तकनीक और अस्पतालों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे महानगरों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस बड़े निजी अस्पताल स्थापित हुए हैं, जहां गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है। इसके बावजूद जब हम ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति देखते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उनकी उपलब्धता के बीच एक गहरी खाई दिखाई देती है। देश के अनेक गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आज भी सामान्य इलाज प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी है। देश के हजारों गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनमें उपलब्ध सुविधाएं अक्सर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होतीं। कई स्थानों पर अस्पतालों के भवन तो मौजूद हैं, लेकिन वहां पर्याप्त डॉक्टर, नर्स, जांच कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहीं हैं। कहीं आवश्यक दवाइयों का अभाव है तो कहीं जांच के उपकरण खराब पड़े हैं। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव और आपातकालीन चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण परिवारों को छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार के लिए भी निजी अस्पतालों या जिला मुख्यालयों का रुख करना पड़ता है। इससे न केवल उनका समय और पैसा खर्च होता है, बल्कि कई बार गंभीर मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और उनकी जान तक चली जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी इस समस्या को और गंभीर बनाती है। चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिकांश डॉक्टर महानगरों और बड़े शहरों में काम करना पसंद करते हैं। इसके पीछे बेहतर वेतन, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, निजी प्रैक्टिस की संभावनाएं, बच्चों की शिक्षा और बेहतर जीवनशैली जैसे कई कारण हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण अस्पतालों में स्वीकृत पद लंबे समय तक खाली पड़े रहते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए केवल डॉक्टरों की नियुक्ति करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का अनुकूल वातावरण भी तैयार करना होगा। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, सुरक्षित आवास, परिवहन, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और उनके परिवारों के लिए शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्रशिक्षण और सेवा के अवसर बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण-शहरी विषमता को कम करने में डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श जैसी सुविधाओं के माध्यम से गांव में बैठे मरीजों को बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मिल सकती है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्च गति के इंटरनेट, आवश्यक डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मचारियों से जोड़ना होगा। यदि किसी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य जांच और प्रारंभिक उपचार की सुविधा उपलब्ध हो तथा जरूरत पड़ने पर मरीज की रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक तक पहुंचाई जा सके, तो उसे बार-बार शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से मरीज की पुरानी बीमारियों, उपचार और दवाइयों का विवरण भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे उपचार की निरंतरता बनी रहेगी और डॉक्टरों को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। हालांकि, तकनीक को पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि उनका सहयोगी माध्यम बनाना होगा। गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों में प्रत्यक्ष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए रोकथाम आधारित चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना भी जरूरी है। स्वास्थ्य का संबंध केवल अस्पतालों और डॉक्टरों से नहीं, बल्कि स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, पोषण, पर्यावरण और नागरिकों की जीवनशैली से भी है। अनेक बीमारियां ऐसी हैं, जिन्हें समय रहते जागरूकता और सावधानियों के माध्यम से रोका जा सकता है। दूषित पानी, खुले में कचरा फेंकने, जलभराव और खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के संक्रमण फैलते हैं। इसलिए गांवों में स्वच्छ पेयजल की नियमित जांच, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और शौचालयों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित भोजन और मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष है। गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सकीय जांच, पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाइयां और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिलना जरूरी है। आज भी अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परिवहन की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार प्रसव के दौरान गंभीर परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव सुविधाओं को मजबूत करना, एंबुलेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसी तरह बच्चों का समय पर टीकाकरण, जन्म के बाद उचित देखभाल और कुपोषण की पहचान भी स्वास्थ्य नीतियों की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करता है।

कुपोषण ग्रामीण भारत की एक ऐसी समस्या है, जिसका सीधा असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। आर्थिक कमजोरी, संतुलित भोजन की कमी और पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार पोषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केवल खाद्य सामग्री वितरित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लाभार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण पोषण पहुंचे और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में वास्तविक सुधार हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इस पूरी व्यवस्था में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे ग्रामीण परिवारों और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती हैं। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के पोषण, परिवार नियोजन और विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। कई बार सीमित संसाधनों और कम मानदेय के बावजूद उन्हें अत्यधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसलिए उनके प्रशिक्षण, मानदेय, कार्यस्थल की सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य तकनीकों से भी परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि वे ग्रामीण समुदायों को बेहतर जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करा सकें। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से समझना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी बीमारियों का बढ़ता प्रभाव भी चिंता का विषय है। पहले सामान्य धारणा थी कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां मुख्य रूप से शहरी जीवनशैली से जुड़ी हैं, लेकिन अब इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। बदलती खानपान की आदतें, शारीरिक गतिविधियों में कमी, तंबाकू का सेवन और नियमित स्वास्थ्य जांच का अभाव इन समस्याओं को गंभीर बनाते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तचाप, मधुमेह और अन्य सामान्य बीमारियों की नियमित जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि केवल बीमारी होने पर अस्पताल जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना भी आवश्यक है। शुरुआती अवस्था में बीमारी की पहचान होने से उपचार आसान और अपेक्षाकृत कम खर्चीला हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक ऐसा पहलू है, जिस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक परेशानियां, बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, सामाजिक दबाव और अन्य परिस्थितियां ग्रामीण आबादी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। किसानों और कृषि श्रमिकों के बीच तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं को भी गंभीरता से समझने की जरूरत है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों में यह जागरूकता पैदा करना भी जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किसी कमजोरी का संकेत नहीं हैं और समय पर सहायता प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक बीमारी का उपचार कराना।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में आर्थिक बाधाएं भी एक बड़ी चुनौती हैं। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए गंभीर बीमारी का इलाज कई बार आर्थिक संकट का कारण बन जाता है। निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च इतना अधिक हो सकता है कि परिवारों को अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। कई परिवार इलाज के खर्च से बचने के लिए बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में स्थिति और गंभीर हो जाती है। सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना जरूरी है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को अस्पताल में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। लेकिन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पात्र व्यक्ति को समय पर जानकारी मिले, अस्पताल में उपचार उपलब्ध हो और भुगतान तथा दावा प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की व्यवस्था से ग्रामीण स्वास्थ्य की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

यह भी समझना होगा कि स्वास्थ्य सेवा ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसे पूरी तरह बाजार की शक्तियों या निजी अस्पतालों के भरोसे छोड़ा जा सके। निजी क्षेत्र की भागीदारी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में सहायक हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की ही है। प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। इसके लिए स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि, अस्पतालों की नियमित निगरानी, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्यकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और स्थानीय स्तर पर शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी आवश्यक है। गांव के लोगों को यह अधिकार और अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, दवाइयों की उपलब्धता और कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रख सकें। स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग के बीच नियमित संवाद से समस्याओं की पहचान और उनका समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाते समय आदिवासी क्षेत्रों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू करने के बजाय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करना अधिक उपयोगी होगा।

# बदलती राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका और जन-विश्वास का गहराता संकट

**संजय प्रकाश**

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया की भूमिका किसी भी जागरूक, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। एक निष्पक्ष और साहसी मीडिया का मुख्य काम केवल सरकार की नीतियों का प्रचार करना या




केवल मनोरंजक सामग्रियां परोसना नहीं होता, बल्कि जनता की समस्याओं को सामने लाना, सत्ता में बैठे लोगों से तीखे सवाल पूछना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और समाज में जन-जागरूकता फैलाना होता है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मीडिया जगत के भीतर जिस प्रकार की व्यावसायिक, राजनीतिक और तकनीकी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, उसने जनता के बीच इसकी साख और विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

आज के समय में अधिकांश मीडिया संस्थानों के बीच विज्ञापनों को पाने की अंधी दौड़, सबसे पहले खबर दिखाने की आपाधापी और दर्शकों की संख्या (टीआरपी) बढ़ाने का एक बहुत ही गंदा खेल चल रहा है। इस होड़ में गंभीर, शोध पर आधारित और जनहित से जुड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता कहीं बहुत पीछे छूट गई है। टीवी चैनलों के समाचार कक्षों में देश के ज्वलंत मुद्दों—जैसे कि बेरोजगारी, किसानों का संकट, गिरती शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और पर्यावरण संकट—पर अर्थपूर्ण और शालीन बहस होने के बजाय, चिल्लाने वाले शो और सनसनीखेज मुद्दों को दिन-रात दिखाया जाता है।

ऐसी खबरों को प्राथमिकता दी जाती है जो समाज में धर्म, जाति या राजनीति के नाम पर ध्रुवीकरण और नफरत पैदा करती हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आसानी से टीआरपी और सुर्खियां बटोरती हैं। इसके साथ ही, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अभूतपूर्व प्रसार ने इस संकट को और अधिक जटिल बना दिया है। आज हर व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वह खुद को सूचना का प्रसारक समझने लगा है। बिना किसी तथ्य की जांच किए, बिना किसी उत्तरदायित्व के और बिना किसी संपादकीय नियंत्रण के भ्रामक खबरें, झूठे दावे और मनगढ़ंत कहानियां जंगल की आग की तरह फैला दी जाती हैं। इस फेक न्यूज के युग में आम नागरिक के लिए यह पहचानना अत्यंत कठिन हो गया है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर किसी विशेष एजेंडे के तहत फैलाई गई है।

मीडिया संस्थानों के मालिकाना हक का कुछ बड़े औद्योगिक घरानों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के हाथों में केंद्रित होना भी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जब मीडिया संस्थान केवल वित्तीय लाभ कमाने या अपने मालिकों के व्यापारिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने का साधन बन जाते हैं, तो वे जनता की आवाज बनना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है और केवल एक जनसंपर्क या प्रचार तंत्र बनकर रह जाती है।

इस गहराते विश्वसनीयता के संकट से उबरने के लिए मीडिया जगत को बहुत ही कठोर और ईमानदार आत्म-समीक्षा करने की आवश्यकता है। पत्रकारों और समाचार पत्रों को अपनी स्थापित पेशेवर आचार संहिता, नैतिक मूल्यों और निष्पक्षता के सिद्धांतों की ओर पुनः लौटना होगा। समाचार और व्यक्तिगत विचारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसके तथ्यों की बहु-स्तरीय जांच-परख अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

पाठकों, दर्शकों और आम नागरिकों की भी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे एक जागरूक और समझदार उपभोक्ता बनें। उन्हें सनसनीखेज, चिल्लाने वाली और भ्रामक खबरों को पूरी तरह से नकारना चाहिए और केवल उन समाचार पत्रों तथा डिजिटल मंचों का समर्थन करना चाहिए जो तथ्य-आधारित, गंभीर और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। जब जनता खुद अच्छी और जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता की मांग करेगी, तो मीडिया संस्थानों को भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।जब तक देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, साहसी और नैतिक रूप से मजबूत मीडिया जीवित रहेगा, तब तक हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित और जीवंत रहेगा। मीडिया को अपनी खोई हुई साख और जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए आज ही से कड़े और सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

# नारी शक्ति के उत्थान से समाज में बदली उनकी भूमिका

**जब तक महिलाएं घर, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक उनकी स्वतंत्र भागीदारी सीमित रहेगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। साथ ही, पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल करने और पीड़ित महिलाओं को कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।**

**सीमा आर्या**

किसी भी देश, समाज या संस्कृति का वास्तविक विकास और उसका नैतिक स्तर इस बात से आंका जाता है कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के कितने समान अवसर प्राप्त हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन समय के साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय महिलाओं ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, कठिन परिश्रम, बौद्धिक क्षमता और साहस के बल पर यह साबित कर दिखाया है कि वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज भारतीय नारियां घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा करने से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक, खेल के मैदानों से लेकर बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम तक और राजनीति के सर्वोच्च पदों तक अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। यह बदलाव केवल महिलाओं की व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय समाज की बदलती सोच और प्रगतिशील दृष्टिकोण का भी परिचायक है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, उद्योग, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। भारतीय बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है और विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सेना और अन्य सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी इस बात का प्रमाण है कि अब उनके लिए अवसरों का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। राजनीति में भी महिलाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण और शहरी प्रशासन में उनकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का अवसर दिया है। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं की समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इस उज्ज्वल तस्वीर के साथ उस कठोर सामाजिक वास्तविकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो आज भी देश के बड़े हिस्से में मौजूद है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अनेक महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, अशिक्षा और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों में आज भी बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उनसे कम उम्र में घरेलू जिम्मेदारियां संभालने की अपेक्षा की जाती है, जबकि बेटों को बेहतर शिक्षा और करियर बनाने के अधिक अवसर दिए जाते हैं। केवल महानगरों की शिक्षित और संपन्न महिलाओं की सफलता को देखकर यह मान लेना उचित नहीं होगा कि पूरे देश में महिलाओं की स्थिति समान रूप से बदल गई है। वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है, जब समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग की महिला को भी सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा को परिवारों की प्राथमिकता बनाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए सुरक्षित विद्यालय, परिवहन, छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वासी, जागरूक और निर्णय लेने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

आर्थिक स्वतंत्रता भी महिला सशक्तिकरण की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक महिला अपनी आवश्यकताओं और जीवन से जुड़े निर्णयों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहेगी, तब तक उसकी वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, कुटीर उद्योगों, आधुनिक कृषि, पशुपालन और लघु व्यवसायों से जोड़कर उनकी आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। उन्हें आसान ऋण, बाजार तक पहुंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पर भेदभाव से सुरक्षा और मातृत्व संबंधी सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। महिलाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें नेतृत्व और निर्णय लेने वाले पदों तक पहुंचने के समान अवसर भी मिलने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न भी सशक्तिकरण की बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक महिलाएं घर, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब तक उनकी स्वतंत्र भागीदारी सीमित रहेगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। साथ ही, पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल करने और पीड़ित महिलाओं को कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पीड़ित महिला को समय पर न्याय मिले और उसे सामाजिक दबाव या अपमान का सामना न करना पड़े। महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कानूनी और आर्थिक सुधार करना। सदियों से चली आ रही पुरुष-प्रधान सोच को बदलना होगा, जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानती है और उनके जीवन के निर्णयों पर नियंत्रण रखना चाहती है। परिवारों में बेटियों को भी बेटों के समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही लड़कों को बचपन से ही महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के संस्कार देना जरूरी है। घरेलू जिम्मेदारियों को केवल महिलाओं का दायित्व मानने की सोच भी बदलनी होगी। परिवार और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की समान भागीदारी से महिलाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकते हैं। महिलाओं की बदलती भूमिका में राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी ने अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व के नए अवसर पैदा किए हैं। अब आवश्यकता है कि महिलाएं केवल प्रतिनिधि बनकर न रहें, बल्कि नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

अंततः यह समझना होगा कि महिलाएं केवल समाज की आधी आबादी नहीं, बल्कि उसकी प्रगति और विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब उसकी महिलाएं शिक्षित, स्वस्थ



## साउथ एक्सेंट पर ट्रोलिंग को लेकर बोलीं ईशा देओल

अभिनेत्री ईशा देओल 15 साल बाद एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म 'प्रताप' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में साउथ इंडियन एक्टर्स के एक्सेंट को लेकर ट्रोल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें साउथ इंडियन एक्सेंट काफी 'प्यारा' और 'क्यूट' लगता है। ईशा ने कहा, 'जब मैं अपने डायलॉग बोलती हूं, खासकर हिंदी में, तो मैं काफी हद तक अपनी मां जैसी लगती हूं, लेकिन असल में मैं वैसी ही हूं और जिन्होंने मुझे किसी खास किरदार के लिए लिया है, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन लोगों का हल्का-सा एक्सेंट सुनना बहुत प्यारा और क्यूट लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है।' अभिनेत्री ने आगे बताया कि बॉलीवुड में भी ऐसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां हैं, जिनकी बोली में साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा, 'और भी कुछ लोगों जैसे श्री आंटी, मेरी मम्मी और उर्मिला में भी साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उर्मिला की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूं और उनकी बोली में जो हल्का-सा एक्सेंट आता है, वो मुझे पसंद है।'

अभिनेत्री ने आगे कहा कि लोगों के बोलने के तरीके का मजाक उड़ाने के बजाय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना जरूरी है। दरअसल, साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर चर्चा तब तेज हो गई जब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में अपने साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर बात की थी।

इस एपिसोड में रश्मिका अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थीं। शो के दौरान रश्मिका ने कहा कि वे दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनके बोलने के लहजे में वहां की झलक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रश्मिका ने यह भी बताया कि वे अपनी फिल्मों के लिए खुद अलग-अलग भाषाओं में डबिंग करने में गर्व महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग उन्हें अपना काम करने से नहीं रोक सकती।



## पहली बार पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी अदिति राव हैदर

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी आगामी पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आएंगी। अभिनेत्री ने बताया कि को-स्टार पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना उनके मजेदार अनुभवों में से एक रहा। अभिनेत्री का कहना है कि पंकज त्रिपाठी का सहज ह्यूमर सीन को हल्का और मजेदार बनाने में मदद करता है। अदिति राव हैदरी ने कहा, 'पंकज जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करना सच में बहुत खुशी की बात थी। उनका ह्यूमर इतना सहज और नेचुरल है कि हर सीन हल्का और ज्यादा मजेदार लगने लगा।' अभिनेत्री इस फिल्म में 'हेलेन' नाम का किरदार निभा रही हैं, जो एक प्रॉपर्टी मैनेजर और हाउसकीपर के रूप में रंजन के घर आती हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने कहा, 'यह एक ऐसी फिल्म है, जिसमें हमारे दर्शकों को रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी फिल्म है, जिसे हमारे दर्शक चाहने वालों के साथ देखना पसंद करेंगे। मुझे इस किरदार के साथ काम करने में बहुत मजा आया है। उसकी खूबियों को और वो अपने आसपास के लोगों से कैसे जुड़ती है, ये सब खोजने में।'

वहीं, पंकज त्रिपाठी ने फिल्म को लेकर कहा, 'मुझे इस फिल्म में इसकी सादगी, किरदारों का असल जिंदगी से जुड़ा होना और ह्यूमर के छोटे-छोटे पल बहुत पसंद आए, जो फैमिली स्टोरीज को खास बनाते हैं। इसमें परिवार की गर्मजोशी है, थोड़ा रोमांस है और वो मजा है जो इसे त्योहारों में देखने के लिए परफेक्ट बनाता है। इस फिल्म का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी अपने चाहने वालों के साथ इस फिल्म को एन्जॉय करें।'

यह फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा का तड़का है। फिल्म का मकसद त्योहारों के मौके पर दर्शकों को एक हल्की-फुल्की फिल्म देना है, जिसे वे अपने परिवार के साथ एन्जॉय कर सकें। 'पारिवारिक मनोरंजन' अदिति और पंकज की साथ में पहली फिल्म है, जो 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगी।

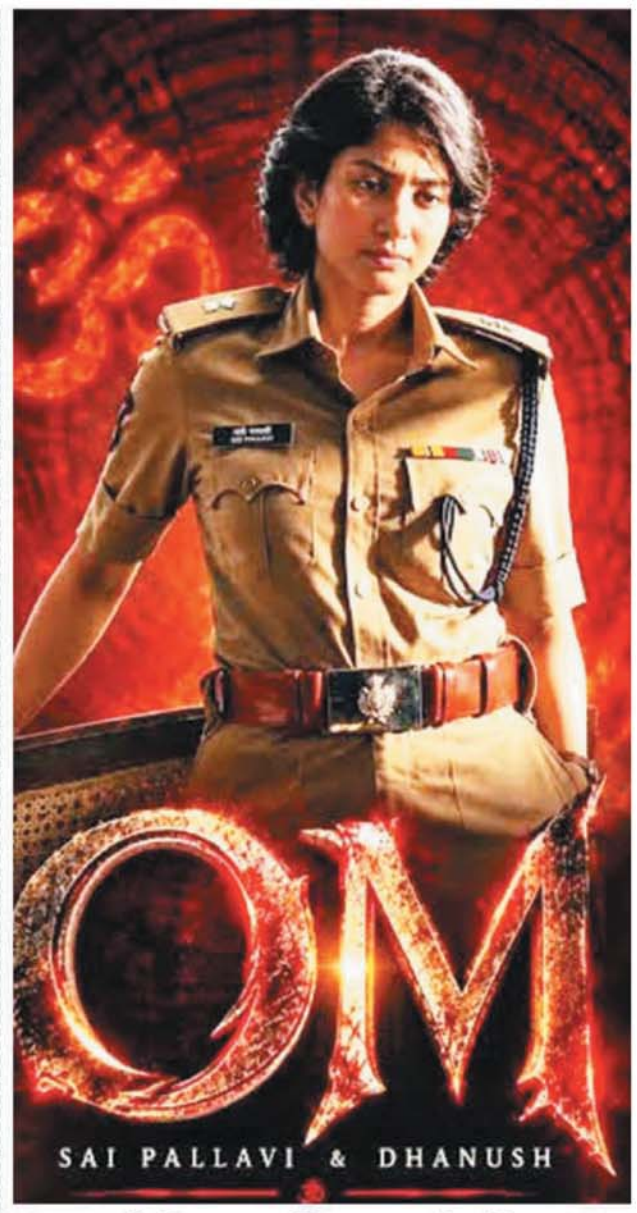


## आईपीएस नित्या रेड्डी बन न्याय के लिए उठाएंगी आवाज़ साई पल्लवी

ओमः चैप्टर 1' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने साई पल्लवी के किरदार आईपीएस नित्या रेड्डी का नया टीजर जारी कर दिया है। टीजर में साई पल्लवी एक बिल्कुल नए और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं, जो धनुष और ममूटी अभिनीत इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में एक नया रोमांच जोड़ता है। अपनी शानदार अदाकारी और सहज पर्दे पर मौजूदगी के लिए मशहूर साई पल्लवी इस बार खाकी वर्दी में नजर आएंगी। 'ओमः चैप्टर 1' के नए टीजर में उनके किरदार की झलक देखने को मिलती है, लेकिन कहानी में उनकी भूमिका क्या मोड़ लेकर आएगी, इसे लेकर निर्माताओं ने फिलहाल रहस्य बरकरार रखा है। साई पल्लवी के अभिनय सफर में यह किरदार एक दिलचस्प नया पड़ाव माना जा रहा है। अपने पिछले किरदारों से अलग, इस बार वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में न्याय के लिए खड़ी नजर आएंगी। भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन कलाकारों से सजी इस फिल्म में उनकी एंट्री ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

फिल्म में साई पल्लवी की भूमिका को लेकर आरटेक स्टूडियोज की निर्माता श्रद्धा अग्रवाल ने कहा, 'साई पल्लवी एक शानदार अभिनेत्री हैं और हम हमेशा से उनकी अदाकारी में नजर आने वाली ईमानदारी और सहजता के प्रशंसक रहे हैं। नित्या रेड्डी फिल्म का एक अहम



किरदार है और इस भूमिका के लिए हमें उनसे बेहतर अभिनेत्री नहीं मिल सकती थी। उन्हें फिल्म से जोड़ना हमारे लिए बेहद खुशी की बात रही है और हम दर्शकों को इस भूमिका में उन्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं।'

राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बन रही 'ओमः चैप्टर 1' में धनुष और ममूटी के साथ साई पल्लवी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आरटेक स्टूडियोज और वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही एक एक्शन थ्रिलर यानी रोमांच और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है। साई पल्लवी के परिचय टीजर के साथ निर्माताओं ने 'ओमः चैप्टर 1' की दुनिया की एक और झलक पेश की है।

## ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर'




अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस की भारतीय शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' को ऑस्कर की रेस में शामिल होने के लिए योग्य हो गई है। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रियंका ने कहा कि यह फिल्म एक समकालीन और महत्वपूर्ण विषय को नए तथा दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करती है। प्रियंका चोपड़ा जोनस इस फिल्म से कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़ी हैं। शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' एक मॉक्यूमेंट्री है, जो भारत के एक छोटे शहर में रहने वाले तीन ऐसे बुजुर्गों की कहानी दिखाती है, जो एआई के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए घरेलू उपकरणों का रूप धारण कर लेते हैं। फिल्म को कई बड़े शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलों में अवॉर्ड मिल चुके हैं। पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल शॉर्टफेस्ट में 'बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म' और 'बेस्ट कॉमेडी शॉर्ट' का पुरस्कार जीतने के बाद यह फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के योग्य हो गई है। अभिनेत्री-प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कहा, 'यह फिल्म एक ऐसे विषय पर मजेदार अंदाज में बात करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। मैं इस क्रिएटिव टीम को सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर तुरंत तैयार हो गई, ताकि उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।'



## बॉलीवुड में किसी को किसी की कद्र नहीं



मनोज बाजपेयी इन दिनों बॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। चार बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके मनोज की पिछली दो फिल्में 'लास्ट मैन इन टावर' और 'गर्वनर' बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई हैं। इन दिनों वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज अपनी फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, इस फिल्म को भी बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। इस बीच 57 साल के एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री को 'एक बड़ा परिवार' मानने वाली आम धारणा को चुनौती दी है। 'गजब रात' के प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि 'यह इंडस्ट्री बकवास है' और यहां किसी को किसी की कोई कद्र नहीं है।

### फिल्म इंडस्ट्री कोई परिवार नहीं, ये भ्रम है

बातचीत में मनोज बाजपेयी ने कहा, 'अगर आप मुझे एक उदाहरण मानना चाहें, तो मैं एक उदाहरण हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसका हिस्सा हूं। जरूरी नहीं कि आप बांद्रा से ही हों। आप मलाड में रहकर भी एक्टिंग कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप जो भी करें, वह अच्छा हो। बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कोई 'परिवार' या 'बिरादरी' जैसी चीज नहीं होती। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह इंडस्ट्री एक परिवार है। यह किसी परिवार की तरह नहीं है। सबके ऑफिस अलग-अलग हैं, कोई किसी के साथ पार्टी नहीं करता और अगर किसी को किसी की फिल्म पसंद आ जाए, तो भी कोई फोन करके तारीफ नहीं करता।'

### यहां कोई किसी की सफलता से खुश नहीं होता

'गजब रात' एक्टर मनोज बाजपेयी ने दो टूक कहा कि इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर किसी दूसरे की सफलता देखकर खुश नहीं होता। कोई भी डायरेक्टर खुद को दूसरे निर्देशक से कम नहीं समझता। कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को ज्यादा पैसे कमाते देखकर खुश नहीं होता। इसलिए, इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।

मैं काम करता हूं, पैसे लेता हूं और घर जाता हूं

साल 2024 में ओटीटी पर रिलीज 'गुलमोहर' के लिए नेशनल अवॉर्ड पाने वाले मनोज बाजपेयी कहते हैं, 'आप अकेले आए हैं और जब आप जाएंगे, तब भी अकेले ही जाएंगे। वैसे, इस तरह की सलाह देने के लिए मैं शायद सही इंसान नहीं हूं। मैं आपको पहले ही यह डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी इस तरह से नहीं मानता। मैं अपना काम करता हूं, अपने पैसे लेता हूं और घर वापस आ जाता हूं।'

### इंडस्ट्री में कोई भाईचारा नहीं कोई मदद के लिए नहीं आता

'सत्या' में भीखू म्हात्रे के किरदार से सिनेमा की दुनिया में चमकने वाले मनोज बाजपेयी ने आगे बताया कि वे अपने काम के तरीके पर न तो आलोचना का असर पड़ने देते हैं और न ही तारीफ का। वह कहते हैं, 'अगर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो कृपया अपने घर पर ही रहें। अगर वे मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, तो मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत दूर रहता हूं। इसलिए कोई लगाव नहीं है। मुझे छोड़िए, इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, चाहे वे कितनी भी बार यह कहें कि 'इंडस्ट्री एक परिवार है' - नहीं, यह सब बकवास है। यहां कोई भाईचारा नहीं है। हम सभी अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आपकी मदद के लिए आ जाए, तो समझ लीजिए कि वह आपका एक अच्छा दिन था, बस इतना ही।'



संक्षिप्त समाचार

## रूसी ड्रोन से बचने गैस पाइपलाइनों में छिपे यूक्रेनी सैनिक

**कीव, एजेंसी।** रूस-यूक्रेन जंग अब अपने पांचवे साल में हैं। ऐसे में रूस के लगातार ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के सैनिकों के लिए जमीन पर खुलेआम चलना मुश्किल कर दिया है। वे पुरानी गैस पाइपलाइनों के अंदर छिपकर रह रहे हैं। करीब 4 फीट चौड़ी इन सुरंगों में सैनिकों को कई हफ्तों से लेकर दो महीने तक गुजारने पड़ते हैं। कभी रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली ये पाइपलाइन अब यूक्रेनी सैनिकों को खाना, हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का रास्ता बन गई हैं। यूक्रेन के कुपियांस्क इलाके में पुरानी गैस पाइपलाइनों का करीब 129 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। पिछले साल के आखिर में रूसी सैनिक इन्हीं पाइपलाइनों के जरिए कुपियांस्क में घुसने में कामयाब हुए थे। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने भी जमीन के नीचे से जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद यूक्रेन की नेशनल गार्ड की खुफिया इकाई ने इन पाइपलाइनों के नक्शे जुटाए। साथ ही, इन्हें बनाने वाले पुराने गैस विशेषज्ञों की मदद से भूमिगत रास्तों का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की। इसके बाद पाइपलाइनों में हवा पहुंचाने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया। यह इस पूरे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा था। इन पाइपलाइनों के जरिए सैनिकों तक खाना और गोला-बारूद पहुंचाया जाता है। इसके लिए छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। दिन में इन गाड़ियों से जरूरी सामान अंदर भेजा जाता है, जबकि रात में खुदाई से निकली मिट्टी की बोरियां बाहर लाई जाती हैं। सैनिक सिर्फ रात में ही कुछ समय के लिए बाहर निकल पाते हैं। सैनिक संकरे रास्तों के कारण घुटनों पर रेंगते हैं इन पाइपलाइनों के अंदर सैनिकों को काफी मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। रास्ते इतने संकरे हैं कि उन्हें झुककर या घुटनों के बल



रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही ताजी हवा मिलती है। शौचालय के लिए सैनिक प्लास्टिक के बैग और बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइनों में गैस के बचे हुए अंश, धूल और हवा की कमी भी उनके लिए खतरा पैदा करती है। घायल सैनिकों को भी इन्हीं रास्तों से बाहर निकाला जाता है। मोर्चे पर मारे गए सैनिकों के शव भी इन पाइपलाइनों के जरिए बाहर लाए जाते हैं। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग तकनीक ने खुले मैदान में सैनिकों की आवाजाही को बेहद खतरनाक बना दिया है। थर्मल इमेजिंग की मदद से ड्रोन जमीन पर मौजूद लोगों के शरीर की गर्मी पहचान सकते हैं। ऐसे में सैनिकों के लिए छिपकर आगे बढ़ना भी आसान नहीं रह गया है। इसी वजह से यूक्रेन अपनी सेना के ठिकानों, निगरानी चौकियों और सामान रखने वाले केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है।

## लंदन में 'फलस्तीन एक्शन' का समर्थन, 139 गिरफ्तार

**लंदन, एजेंसी।** लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रतिबंधित 'फलस्तीन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 139 लोगों को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों ने एक प्रतिबंधित संगठन का समर्थन किया था। 'डिफेंड आवर जूरीज' के अनुसार, जुलाई 2025 से प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 4,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। ब्रिटेन सरकार ने पिछले साल 'फलस्तीन एक्शन' को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जिसके समर्थन पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। शनिवार को लंदन में यह प्रदर्शन 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में समूह के आतंकवादी पदनाम के खिलाफ अपील से पहले हुआ। अगस्त में, अमेरिकी सरकार ने भी इस समूह पर प्रतिबंध लगाए थे। 2020 में स्थापित 'फलस्तीन एक्शन' का लक्ष्य इस्राइल को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन से रोकना है, जिसे वह फिलिस्तीनियों का नरसंहार मानती है।

# जर्मनी में हैलोवीन की वेशभूषा में लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन

**बर्लिन, एजेंसी।** जर्मनी के 34 से अधिक शहरों जैसे कि बर्लिन, फ्रैंकफर्च, म्यूनिख और कोलोन में शनिवार को हजारों युवा सड़कों पर उतरे। लट्ठ रेगेल्ट यानी लट्ठ अब कमान संभालेगी नामक इस युवा अभियान के तहत आयोजित इन प्रदर्शनों का मकसद बढ़ती महंगाई, शिक्षा के बजट में कटौती और सेना को मजबूत करने की सरकारी योजनाओं का विरोध करना था।

बता दें कि यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब देश में हैलोवीन का जश्न भी मनाया जा रहा था, लेकिन दिन ढलते-ढलते शांतिपूर्ण दिखने वाला यह आंदोलन कई जगहों पर भीषण हिंसा और आगजनी में बदल गया।

महंगाई और बजट कटौती- देश की सुस्त अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार द्वारा शिक्षा, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती करना युवाओं को नागवार गुजरा है। सैन्य खर्च और अनिवार्य सैन्य सेवा- युवा सरकार की उस योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं जिसके तहत सैन्य बलों की संख्या बढ़ाने और

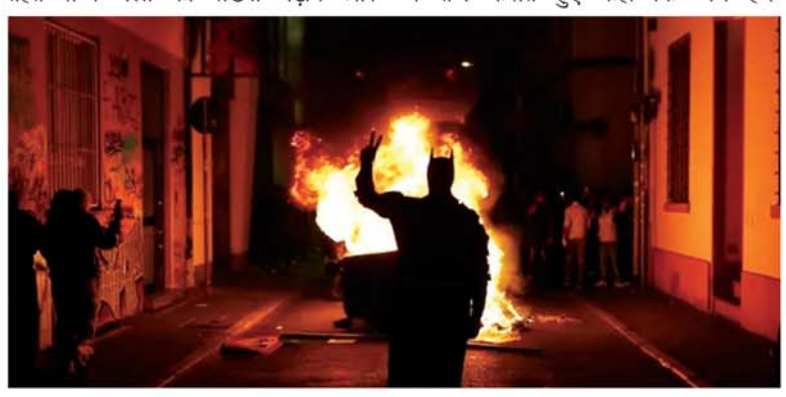

अनिवार्य सैन्य सेवा को दोबारा लाने की बात की जा रही है।

**भविष्य की चिंता-** देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के बीच कामकाजी युवाओं पर टैक्स और आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज की खस्ता हालत पर एक छात्र ने तंज कसते हुए कहा कि जब हम यूनिवर्सिटी के कमरों के अंदर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी खंडहर में आ गए हों। इस बात को ऐसे समझिए कि दिन के समय तो प्रदर्शन काफी हद तक शांत रहे, लेकिन शाम होते ही फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग और कोलोन जैसे बड़े शहरों में हालात बेकाबू हो गए। फ्रैंकफर्ट में नकाबपोश उपद्रवियों ने कई दुकानों और एक गन स्टोर के शीशे तोड़कर लूटपाट की। परफ्यूम स्टोर और ट्रेनर शॉप को भी निशाना बनाया गया।

इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि उग्र भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों और आपातकालीन सेवाओं पर पत्थर, आतिशबाजी और पेट्रोल बम फेंके। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रशासन और स्थानीय मंत्रियों ने इस हिंसा के लिए बाहरी और चरमपंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। हेसे राज्य के आंतरिक मंत्री रोमन पोसेक ने कहा कि फ्रैंकफर्ट के प्रदर्शनों में करीब 100 कट्टर वामपंथी घुसपैठ कर गए थे, जिन्होंने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में बदल दिया। हालांकि इससे पहले जर्मन अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि फ्रांस में हुए दंगों की तर्ज पर जर्मनी में भी अति-वामपंथी और विदेशी चरमपंथी समूह माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। उधर, लट्ठ रेगेल्ट आंदोलन के आयोजकों ने हिंसा से पूरी तरह किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि हमारे आंदोलनों में किसी भी तरह के चरमपंथी समूहों, नस्लवाद और नफरत भरे भाषणों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा गौर करने वाली बात यह है कि आयोजकों को शुरुआत में करीब 1.80 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में लगभग 120000 लोग ही इसमें शामिल हो पाए। इस आंदोलन को पूरी तरह छात्र-नेतृत्व वाला बताने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जर्मनी के राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इस अभियान से खुद को अलग कर लिया है और 20 नवंबर को एक अलग विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिससे यह साफ होता है कि युवाओं के मुद्दों को उठाने के तरीकों को लेकर खुद उनके बीच मतभेद हैं।

# टैक्स देने में की गड़बड़ी तो अमेरिका में रहने की चाहत रह जाएगी अधूरी, ग्रीन कार्ड के लिए सख्त हुए नियम

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका में बसने की चाहत रखने वालों को टैक्स नियमों का पालन करना होगा। टैक्स नियमों का पालन ना करने का असर नागरिकता आवेदन पर दिख सकता है। इसको लेकर इमिग्रेशन वकीलों ने चेतावनी जारी की है। यूएससीआईएस का एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस (ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया) को लेकर अपनाया गया सख्त और विवेकाधीन रवैया, आवेदकों और कुछ मामलों में उनके वित्तीय प्रायोजकों को और अधिक गहन जांच के दायरे में लाता है। टैक्स नियमों का पालन न करने का असर भविष्य में नागरिकता के आवेदनों पर भी पड़ सकता है।

मई में अमेरिका के सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से जारी एक नीतिगत ज्ञापन में एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत अमेरिका में पहले से मौजूद पात्र विदेशी नागरिक स्थायी निवास के लिए अप्लाई करते हैं।

अब इसमें बदलाव करते हुए इसे एक विवेकाधीन लाभ माना जाएगा। इस नीति के तहत यूएससीआईएस अधिकारियों को यह

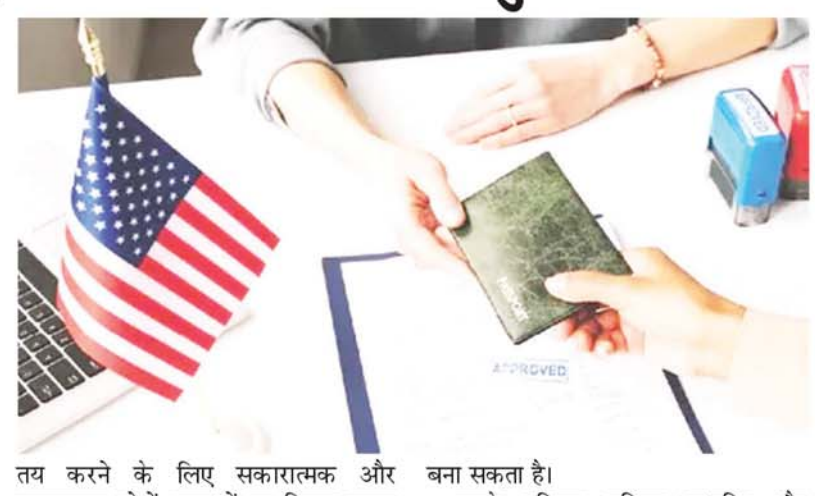

तय करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा कि क्या आवेदक को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।

इमिग्रेशन वकीलों ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि टैक्स का भुगतान न करना, रिटर्न फाइल न करना, या यहां तक कि टैक्स चुकाने की तय योजना के तहत केवल आंशिक भुगतान करना भी, किसी अप्रवासी के ग्रीन कार्ड आवेदन को मुश्किल बना सकता है।

इसके परिणाम परिवार-आधारित और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों, तथा अपने रिश्तेदारों को प्रायोजित करने वाले अमेरिकी नागरिकों, सभी पर पड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क स्थित इमिग्रेशन वकील, कैरिन वोलमैन का कहना है कि जो कोई भी, हर के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहा है उसे पहले अपने टैक्स रिकॉर्ड पर विशेष ध्यान देना होगा।

# घड़ी के शीशे बनाने वाली झोउ छुनफेई अब चीन की सबसे अमीर महिला बनीं

**बीजिंग, एजेंसी।** चीन की एक महिला ने फैक्टरी में काम करने से लेकर देश की सबसे अमीर महिला बनने तक का सफर तय किया है। 56 साल की झोउ छुनफेई ने किशोरावस्था में ही स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने एक फैक्टरी में काम शुरू किया। आज वह ग्लास बनाने वाली कंपनी लेंस टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 1.27 लाख करोड़ युआन यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये है। 28 अक्तूबर को जारी हुरुन की 2026 की चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में झोउ ने फिर पहला स्थान हासिल किया है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति 15 बढ़ी है। एपल के आईफोन से बदली किस्मत झोउ को बड़ी कामयाबी 2007 में मिली, जब उसे एपल के शुरुआती आईफोन के लिए ग्लास कवर बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद एपल का कारोबार लेंस की कमाई का बड़ा स्रोत बन गया। हुरुन एक वैश्विक शोध और प्रकाशन संस्थान है, जो 1999 से चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी कर रहा है। यह सूची चीन के सबसे अमीर लोगों की समग्र सूची से अलग है। इसमें परिवारों या दंपतियों की संयुक्त संपत्ति के बजाय महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति का



आकलन किया जाता है, जिसे परिवार की संपत्ति से अलग पहचाना जा सके।

झोउ छुनफेई का जन्म 1970 में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। किशोरावस्था में स्कूल छोड़ने के बाद वह शेनझेन चली गईं। वहां उन्होंने घड़ियों के शीशे बनाने वाली फैक्टरी में काम किया। इस काम के लिए उन्हें रोजाना करीब 1.20 डॉलर यानी लगभग 114 रुपये मिलते थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने शीशे की प्रोसेसिंग करने की अपनी वर्कशॉप शुरू की। उन्होंने खुद ही आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें सीखीं और धीरे-धीरे अपना कारोबार बढ़ाया।

# नवंबर में भारत आ सकते हैं नेपाल के पीएम बालेन शाह, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

**काठमांडु , एजेंसी।** भारत-नेपाल के तनाव के बीच अच्छी खबर आ रही है। जल्द ही दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर आने वाले हैं। नवंबर के आखिरी में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा प्रस्तावित है।



इससे पहले बालेन शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा का एजेंडा तैयार करने के लिए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के चार नवंबर को काठमांडू पहुंचने की उम्मीद है। यह यात्रा कई महीनों के राजनयिक तनाव के बाद हो रही है। इसमें मिसरी की एक प्रस्तावित यात्रा का टल जाना और लिपुलेख को लेकर मतभेद जैसी घटनाएं शामिल हैं।

नवंबर में पीएम बालेन शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान नेपाल बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण, जलविद्युत क्षेत्र में नए निवेश और अटकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए भारत से वित्तीय सहायता मांग सकता है। भारत से वित्तीय मदद मिलने के बाद वहां की लटकी परियोजनाओं में तेजी आ सकती है।

काठमांडू चाहता है कि भारत की ओर से वित्तीय सहायता मिले। इस दौरे से वित्तीय प्रतिबद्धताओं को तेजी मिले मिलें। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो और उन परियोजनाओं पर प्रगति हो जो पहले हुए समझौतों के बावजूद अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही दोनों देश ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं, जिनका उद्घाटन या शुरुआत इस दौरे के दौरान की जा सकती है। शाह का दौरा नवंबर के उत्तरार्ध में होने की उम्मीद है, हालांकि तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। भारत के नए राजदूत सुधाकर दलेला के 3 नवंबर को काठमांडू पहुंचने की संभावना है, जो मिसरी के प्रस्तावित आगमन से एक दिन पहले होगा। प्रधानमंत्री के दौरे का एजेंडा तय करने के लिए विदेश सचिव नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

# भूटान में पवित्र स्तूपों के निर्माण में शामिल होने पहुंचे किरेन रिजिजू, बताया ऐतिहासिक क्षण

**थिम्फू, एजेंसी।** करुणा के मंत्र और पारंपरिक तुरहियों की गूंज के साथ भूटान में स्तूपों के निर्माण की शुरुआत होगी। इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को होगी।

भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 जंगचूब चोर्टेन (स्तूपों) के निर्माण की शुरुआत होगी। इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत 58 पारंपरिक तुरहियों (ट्रम्पेट्स) की गूंज के साथ होगी। इसे आत्माओं और देवताओं के आह्वान करने के लिए बजाया जाता है। इसके साथ ही करुणा के मंत्र ओम मणि पद्मे हुम का सामूहिक जाप भी होगा।

यह मंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध है और इसका व्यापक रूप से जाप किया जाता है। इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम दाशो शेरिंग तोबगे, विदेश मंत्री ल्योंपो डी. एन. ढुंगेल, विदेश सचिव, और भूटान तथा भारत के राजदूतों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

**108 स्तूपों के निर्माण के बनेंगे साक्षी ल** उन्होंने कहा कि वो 108 स्तूपों (जंगचूब चोर्टेन) की स्थापना के भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए गेलेफू जा रहे हैं। यह पहल भूटान के महामहिम राजा



की परिकल्पना है। यह गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का क्षण है। इस दौरान जब रिजिजू समारोह के लिए गेलेफू पहुंचे, तब भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने खुद गाड़ी चलाई। इस पर रिजिजू ने इस क्षण को बहुत ही सम्मान की बात बताया।

**बन सकता है गिनीज रिकॉर्ड:** भूटान के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में एक ही जगह पर एक साथ 108 स्तूपों की स्थापना और उनका अभिषेक किया जाएगा। इसको लेकर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद गिनीज रिकॉर्ड भी बन सकता है।

**बौद्ध धर्म का पवित्र समारोह:** इस प्रक्रिया और समारोह की महत्ता को बताते हुए भूटान के आधिकारिक राज्य मठ निकाय सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी के प्रधान सचिव चोटेन दोरजी ने बताया कि यह वज्रयान बौद्ध धर्म का एक पवित्र समारोह है, जिसे स्वयं बुद्ध के जागृत होने के रूप में देखा जाता है। एक स्तूप को दिव्य शक्ति से संपन्न होकर एक पवित्र स्मारक बनने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया रविवार स्तूपों की स्थापना के साथ शुरू होती है और उनके पूरा होने के बाद उनका अभिषेक किया जाता है।

स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म की एक पवित्र प्रथा है, जिसमें ऐसे वास्तुशिल्प स्मारक बनाए जाते हैं जो बुद्ध के प्रबुद्ध मन, शरीर और चेतना के प्रतीक होते हैं। यह परंपरा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण (निधन) के तुरंत बाद शुरू हुई थी। बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद बचे अवशेषों को आठ हिस्सों में बांटा गया और उन्हें आठ मिट्टी के टीलों के नीचे दबा दिया गया। सम्राट अशोक ने इन मूल अवशेष वाले टीलों को खुलवाया, बुद्ध के अवशेषों को 84,000 हिस्सों में विभाजित किया और पूरे साम्राज्य में बड़े पैमाने पर स्तूपों के निर्माण की शुरुआत की।

# एस.जयशंकर: 'क्वाड देशों में चुनने की आजादी जरूरी', सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा पर और क्या बोले विदेश मंत्री

**अटलांटा , एजेंसी।** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को क्वाड के लिए 'चुनने की स्वतंत्रता', मजबूत सप्लाई चेन और गैर-बाजार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही, उन्होंने इस समूह के एजेंडे के लिए एक अधिक समकालीन और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में जयशंकर ने उन प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया, जिन पर उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ चर्चा की थी।

समूह की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, समृद्धि को बढ़ावा देना और पसंद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धताएं हैं।' उन्होंने टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

जयशंकर ने चर्चा के दौरान उठाई गई प्राथमिकताओं में इंडो-पैसिफिक में गैर-बाजार प्रथाओं का मुकाबला करने और बढ़ते आर्थिक दबावों को भी शामिल किया। हालांकि, उनकी पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया गया और न ही यह बताया गया कि किन विशिष्ट प्रथाओं की बात हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़े मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि मजबूती बढ़ाई जा सके और शांति व स्थिरता को समर्थन मिले। मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी



डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की इच्छा जताई। इसमें 'क्वाड एआई एक्सेलेरेटर' के माध्यम से दी जाने वाली मदद भी शामिल है। विज्ञप्ति में सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ एक फुटनोट में स्पष्ट किया गया है कि यह शब्द भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। मंत्रियों ने भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की सुविधाओं के लिए वाशिंगटन द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के वादे का स्वागत किया। यह राशि केवल भारत के लिए नहीं है।

ये चारों साझेदार देश, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से खनिज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके। वे रीसाइकल होने वाली सामग्रियों को एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। समुद्री सहयोग के तहत, चारों देशों के प्रतिनिधियों ने 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच चेन्नई से पर्थ तक भारतीय तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज पर यात्रा की।

# जापान के तट के पास 6.0 तीव्रता का भूकंप

**टोक्यो, एजेंसी।** जापान के मी प्रांत के तट के पास रविवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र भूकंप का केंद्र मी प्रांत की राजधानी त्सु से करीब 110 किलोमीटर दक्षिण में था। त्सु की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है। भूकंप समुद्र में जमीन से 352 किलोमीटर की गहराई में आया। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। फिलहाल किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर की वेबसाइट पर लोगों ने बताया कि झटके काफी देर तक महसूस हुए। शुरुआत में हल्के झटके लगे, जो धीरे-धीरे तेज होते गए। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह चार बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है और प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' का हिस्सा है। हर साल यहां करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्के होते हैं। जापान के नोटो द्वीप में 2024 में आए भूकंप में करीब 600 लोग मारे गए थे। 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने 18 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।



# मेरी डिक्शनरी में डर शब्द नहीं: गंभीर

## कप्तान अय्यर ने कहा- गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत

**नई दील्ली।** भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 3-2 से हराया। सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, मेरी डिक्शनरी और डायरेक्टरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं है। गंभीर ने पहले मैच का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि टीम ने 15 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद सिर्फ एक अभ्यास सत्र किया था, इसके बावजूद मुकाबला जीत लिया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को सीरीज का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने पांच मैचों में 341 रन बनाए।

- **ध्यान अब वनडे सीरीज पर: अय्यर** - अय्यर के मुताबिक, न्यूजीलैंड में खेलने के दौरान खिलाड़ियों को अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आसमान में साफ रोशनी और मैदान पर अंधेरे जैसी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां भारत में आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं। कप्तान ने यह भी कहा कि टीम इन कमियों पर चर्चा करेगी। हालांकि, उनका ध्यान अब वनडे सीरीज पर है और खिलाड़ी अच्छे मूड में हैं।
- **ऋषभ पंत की चोट पर गंभीर के पास अपडेट नहीं** - प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर से ऋषभ पंत की उपलब्धता को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास पंत की चोट को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है।

### थकान के बावजूद जीत हासिल की

गंभीर ने कहा, विदेशी परिस्थितियों में खेलते समय टीम को मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लंबी यात्रा और कम अभ्यास का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पहले मैच में जीत हासिल करना आसान नहीं था। गंभीर ने इसी प्रदर्शन को टीम की मानसिक मजबूती का उदाहरण बताया। सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों में भारत ने लगातार जीत दर्ज की। इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए आखिरी दोनों मैच अपने नाम किए।

### सीरीज का नतीजा उलटा भी हो सकता था- सैंटनर

*न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माना कि सीरीज काफी करीबी रही। उनके मुताबिक, शुरुआती दो मुकाबलों में कुछ ऐसे मौके आए, जिन्हें न्यूजीलैंड भुना सकता था। अगर टीम उन मौकों पर बेहतर प्रदर्शन करती, तो सीरीज का नतीजा भारत के बजाय न्यूजीलैंड के पक्ष में भी हो सकता था। सैंटनर ने गेंदबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आखिरी दो मैचों में गेंदबाजों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदली। तेज गेंदबाजों ने यॉर्कर, वाइड गेंदों और सही लेंथ का इस्तेमाल किया।*



# एंटोनेली बने सबसे कम उम्र के एफ-1 चैंपियन

**नई दिल्ली।** किमी एंटोनेली नेइतिहास रचते हुए फॉर्मूला वन के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 20 वर्षीय मर्सिडीज ड्राइवर ने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टापेन और लुईस हैमिल्टन के बाद तीसरे स्थान पर रहकर यह उपलब्धि प्राप्त की।

किमी, जो फॉर्मूला वन रेसिंग में अपने दूसरे ही सीजन में हैं, ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2010 में अपनी चार ड्राइवर चैंपियनशिप में से पहली चैंपियनशिप जीतने के समय 23 साल और 133 दिन के थे। अपनी उपलब्धि की वास्तविकता को समझते हुए किमी अपने आँसू रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

टीम रेडियो पर, नव-ताजपोश विश्व चैंपियन पहले तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मर्सिडीज को अपने सपने को साकार करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। 'हमने कर दिखाया! हमने कर दिखाया!' उसे हंसते-हंसते आंसुओं के साथ कहते हुए सुना गया। इसके बाद जो जश्न मनाया गया, वह इस अवसर के अनुरूप ही था।

पोडियम पर एंटोनेली अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी वर्स्टापेन और हैमिल्टन ने भी उनका साथ दिया और नव-प्रतिभाशाली चैंपियन को हवा में उठा लिया। यह एक यादगार दृश्य था: खेल के दो महानतम ड्राइवर फॉर्मूला वन चैंपियन की नई पीढ़ी के आगमन का जश्न मना रहे थे। मैं भविष्य में और अधिक मुकाबलों के लिए उत्सुक हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'यह तो बस शुरुआत है।' एंटोनेली के लिए, यह सात साल के कार्टिंग के शौकीन से लेकर मोटरस्पोर्ट के शिखर तक की एक उल्लेखनीय यात्रा की परिणति थी।



# दिल्ली में नहीं खेल पाएंगे विराट कोहली

## श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे की मेजबानी पर संकट

**नई दिल्ली:** भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली को अपने घरेलू मैदान दिल्ली में खेलते हुए देखने का इंतजार कर रहे फैंस को निराशा हाथ लग सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की मेजबानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से छिन सकती है। हालांकि, बीसीसीआई की ओर से वेन्यू बदलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

**विराट कोहली की दिल्ली वापसी का इंतजार कर रहे थे फैंस** - विराट कोहली के लिए दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम बेहद खास है। इसी मैदान और दिल्ली के घरेलू क्रिकेट से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2019 में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए स्टेडियम के एक प्रमुख स्टैंड का नाम 'विराट कोहली पवेलियन' रखा था। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में होने वाला वनडे मुकाबला स्थानीय फैंस के लिए कोहली को अपने घरेलू मैदान पर देखने का शानदार अवसर हो सकता था।

- **आउटफील्ड के निर्माण कार्य के कारण बदला जा सकता है वेन्यू** - दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस समय आउटफील्ड को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है। डीडीसीए ने मैदान में सैंड बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का फैसला किया है। इस तकनीक से बारिश के बाद मैदान से पानी तेजी से निकल सकेगा और मैच दोबारा शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे काम को पूरा होने में करीब चार महीने लगेंगे और स्टेडियम आईपीएल 2027 से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

### अरुण जेटली स्टेडियम में आखिरी वनडे कब खेला गया था?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला 11 अक्टूबर 2023 को खेला गया था। यह आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला था, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराया था। फिलहाल स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते दिल्ली की घरेलू टीम को भी अपने रणजी ट्रॉफी मुकाबले पालम स्थित एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेलने पड़ रहे हैं।

### न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी में जुटे विराट कोहली

दूसरी ओर विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। टी20 सीरीज खत्म होने के बाद वह न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद कोहली का फोकस अब मुख्य रूप से वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर है।

# सिंधू ने जीता हाइलो ओपन का खिताब



**जर्मनी:** भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। सिंधु ने जर्मनी में खेले गए हाइलो ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में डेनमार्क की लाइन केजर्सफेल्ट को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिंधु ने मौजूदा सीजन का अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है।

**पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहीं सिंधु** - सिंधु का हाइलो ओपन में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने फाइनल तक के सफर में एक भी गेम नहीं गंवाया। अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने भारतीय खिलाड़ी प्रकृति भरत को हराकर की। इसके बाद फ्रांस की रोजी ओक्टाविया पंकासारी और जर्मनी की अमाली शुल्ज को मात देकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उन्होंने भारत की ही अनमोल खरब को 21-13, 21-16 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया।

### फाइनल जीतकर बनीं चैंपियन

पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पहला गेम महज 17 मिनट में 21-12 से जीतकर डेनमार्क की खिलाड़ी पर दबाव बना दिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी सिंधु ने अपनी लय बरकरार रखी और 21-14 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय शटलर ने यह फाइनल केवल 39 मिनट में जीतकर शानदार अंदाज में खिताब पर कब्जा किया।

### जापान ओपन के बाद अब हाइलो ओपन पर कब्जा

पीवी सिंधु के लिए यह साल खिताब के लिहाज से शानदार रहा है। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन 2026 के फाइनल में जापान की तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता था। अब हाइलो ओपन जीतकर उन्होंने इस सीजन का दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया है।

### विश्व टूर फाइनल्स की राह हुई मजबूत

हाइलो ओपन का खिताब जीतने के साथ ही सिंधु को 9200 रैंकिंग अंक मिले हैं। इससे साल के आखिर में होने वाले विश्व टूर फाइनल्स में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को मजबूती मिली है। दुनिया की आठवें नंबर की भारतीय खिलाड़ी के लिए यह जीत सीजन के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। सिंधु के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने का दम रखती हैं।

# सेंथिलकुमार ने चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह

**ब्रनो।** भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने ब्रनो में चल रहे चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 35,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस पीएसए कॉपर-लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी और विश्व नंबर 32 ऑगस्ट डुसॉर्ड को हराया। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को 11-7, 12-10, 11-1 से मात दी। चौथे वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अब फाइनल में स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन (जो शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और विश्व रैंकिंग में 31वें नंबर पर हैं) का सामना करेंगे। सेंथिलकुमार इस सीजन में अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त लोबन ने फ्रांस के तौफिक मेखल्फी को 11-9, 11-5, 11-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले, सेंथिलकुमार ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहले गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को आसानी से 11-3 से हराया।

# फ्रैंकफर्ट ने हैम्बर्गर को 3-1 से हराया, टॉप-8 में हुई एंट्री

**बर्लिन।** आइनट्राख्त फ्रैंकफर्ट ने हैम्बर्गर एसवी को 3-1 से हराकर बुंडेसलिगा लीग में आठवां स्थान हासिल कर लिया है। जर्मन कप में जीत के बाद पांच दिनों के भीतर हैम्बर्ग के खिलाफ यह उनकी दूसरी जीत है। 59 हजार दर्शकों के सामने फ्रैंकफर्ट ने शानदार शुरुआत की और 10वें मिनट में ही बढ़त बना ली। कैन उजुन ने पेनल्टी एरिया में फेरेस चैबी को गेंद पास की, जिसे हैम्बर्ग के डिफेंडर वार्मड ओमारी ने रोकने की कोशिश में अपनी ही गोल पोस्ट में डाल दिया। चार मिनट बाद हैम्बर्ग ने बराबरी कर ली। लिलियन ब्रासियर, मिरो मुहेम की गेंद को ठीक से नहीं संभाल पाए, जिसका फायदा उठाते हुए अल्बर्ट ग्रोनबेक ने टेरेम मोफी को पास दिया। मोफी ने करीब से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम से ठीक पहले फ्रैंकफर्ट के कप्तान रॉबिन कोच ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर डैनियल ह्यूअर फर्नांडीस ने उनके हेडर को बाहर धकेल दिया। हाफ टाइम के तुरंत बाद फ्रैंकफर्ट ने फिर से बढ़त बना ली। चैबी के कॉर्नर पर ब्रासियर ने हेडर लगाया, जिसे ह्यूअर फर्नांडीस पूरी तरह रोक नहीं पाए। रिबाउंड पर राफेल ओन्येदिका ने 47वें मिनट में गोल किया।

# मेसी का शानदार खेल, न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन को हराया



**फॉक्सबोरो।** लियोनेल मेसी ने एक बेहतरीन असिस्ट और मैच के आखिर में किए गए गोल की मदद से इंटर मियामी को न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के खिलाफ 2-1 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही टीम ने अगले साल होने वाले कॉन्काकैफ चैंपियंस कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत से मियामी एमएलएस कप प्लेऑफ से पहले ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में नंबर 2 सीड की स्थिति में पहुंच गई है। इस सीजन में मेसी के नाम अब 26 गोल और 16 असिस्ट हो गए हैं। इसके साथ ही वह लगातार तीसरी बार एमएलएस एमवीपी अवार्ड और लगातार दूसरी बार 'गोल्डन बूट' जीतने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं।

पहले 45 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला रहा और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस दौरान इंटर मियामी को 28वें मिनट में एक अच्छा मौका मिला, जब मेक्सिकन खिलाड़ी बर्टेरामे ने बॉक्स के बाईं ओर से बाएं पैर से शॉट मारा, जिसे न्यू इंग्लैंड के गोलकीपर मैट टर्नर ने बचा लिया। दूसरे हाफ में, 53वें मिनट में डेनियल गाजदाग के गोल की बदौलत मेजबान टीम (न्यू इंग्लैंड) ने खाता खोला।

### 83वें मिनट में मियामी ने पासा पूरी तरह से पलटा

69वें मिनट में इंटर मियामी ने शानदार टीम वर्क दिखाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। सेगोविया ने बॉक्स के अंदर एक 'लॉब' पास दिया, जिस पर मेसी ने हेडर से गेंद को बर्टेरामे की तरफ बढ़ाया। बर्टेरामे ने बॉक्स के बीच से एक जोरदार हेडर लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। यह इस रेगुलर सीजन में बर्टेरामे का 10वां गोल था, जबकि मेसी का यह इस लीग सीजन का 16वां असिस्ट रहा। 83वें मिनट में इंटर मियामी ने मैच का पासा पूरी तरह से पलटा। एक बेहतरीन पासिंग सीक्वेंस के बाद मेसी ने निर्णायक गोल किया। सुआरेज ने बॉक्स के बाहर बीच में मेसी को गेंद दी, जहां अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी ने तीन डिफेंडरों को छकाया। इसके बाद सेगोविया के साथ मिलकर वह बॉक्स के अंदर पहुंचे और एक सटीक शॉट के जरिए गेंद को गोल पोस्ट के निचले दाएं कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ मेसी के कुल गोल की संख्या 26 हो गई है, जिससे वह एमएलएस 2026 गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। वहीं, इस रेगुलर सीजन में सेगोविया के असिस्ट की संख्या 12 हो गई है। इसके बाद 1-2 की स्कोरलाइन अंतिम सीटी बजने तक कायम रहा, जिससे इंटर मियामी ने अपने घर से बाहर खेलते हुए तीन अंक हासिल किए।

# किसानों की मांग पर झुका प्रशासन, उतई सोसायटी का घेराव कर जमीन पर बैठे किसान

## दाऊ चंद्रशेखर चंद्राकर के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

### तहसीलदार ने मौके पर ही दिए निर्देश; अब सोसायटी में ऑफलाइन भी जमा होंगे बीमा आवेदन

मूक पत्रिका





**उतई।** अनंव चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने दाऊ चंद्रशेखर चंद्राकर के नेतृत्व में उतई वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति का घेराव किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान सोसायटी परिसर में जुटने लगे। अपनी मांगों को लेकर किसान जमीन पर बैठ गए और प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखीं। किसानों की समस्याओं को सुनने पहुंचे नायब तहसीलदार वासु धर दीवान भी किसानों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनीं। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही सोसायटी प्रबंधक एवं बीमा कंपनी को किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। प्रशासन के आश्वासन के बाद अब किसानों को ऑफलाइन माध्यम से भी बीमा आवेदन जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सोसायटी में जल्द ही हेल्प डेस्क बनाए जाने की बात कही गई है।

ये रही किसानों की प्रमुख मांगें

1. बारिश से प्रभावित फसलों का जल्द सर्वे कराकर किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाए।

2. बीमा कंपनी द्वारा केवल ऑनलाइन या फोन के माध्यम से आवेदन लेने के बजाय ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएं।

3. किसानों की सुविधा के लिए बीमा आवेदन सोसायटी के माध्यम से जमा कराए जाएं।

4. बारिश से प्रभावित फसलों के बीमा संबंधी आवेदन सोसायटी के माध्यम से ही लिए जाएं, ताकि किसानों को परेशानी न हो।

**सुबह से ही सोसायटी में जुटने लगे किसान**-किसानों के घेराव को लेकर सुबह से ही उतई सोसायटी परिसर में बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे। दाऊ चंद्रशेखर चंद्राकर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में दाऊ लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, अशोक साहू, तुलूराम साहू, बिसेलाल, पार्षद रोहित धनकर, संजय साहू, भगवानी साहू, भागवत देवांगन, तोमन साहू, मंतराम साहू, अरुण वर्मा, प्रहलाद वर्मा, जागेश्वर साहू, तहसीलदार वासु धर दीवान, फटेलाल वर्मा, गिरधर सोनी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

**सोसायटी में बनेगा हेल्प डेस्क, ऑफलाइन भी जमा होंगे आवेदन : तहसीलदार**-नायब तहसीलदार वासु धर दीवान ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बारिश से निश्चित रूप से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान बीमा के लिए परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन एवं फोन के माध्यम से आवेदन करने में किसानों को आ रही दिक्कतों की शिकायतें मिली हैं। किसानों की मांग को देखते हुए जल्द ही सोसायटी में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

**-वासु धर दीवान, नायब तहसीलदार, दुर्ग**

# युवा रत्न सम्मान योजना: आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर तक बढ़ी

## पात्र युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को मिला अतिरिक्त अवसर

मूक पत्रिका





बेमेतरा ,3 नवम्बर 2026/संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा संचालित युवा रत्न सम्मान योजना 2026-27 अंतर्गत पात्र युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है।संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 01 से 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। जिलों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अधिकाधिक पात्र युवाओं को आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 नवंबर 2026 तक कर दिया गया है।

संशोधित समय-सारणी इस प्रकार है -

- जिला स्तरीय समितियों द्वारा आवेदन आमंत्रणः 01 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक
- आवेदन का परीक्षणः 16 से 30 नवंबर 2026
- संचालनालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथिः 01 से 15 दिसंबर 2026
- अंतिम सूची की घोषणाः 01 जनवरी 2027
- पुरस्कार वितरणः 12 जनवरी 2027 (युवा दिवस पर)

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के पात्र युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों से अपील की है कि जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इस बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाते हुए 15 नवंबर तक अपना आवेदन जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

# जिला स्तरीय राज्योत्सव में जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी

## जनमन पत्रिका का किया गया निःशुल्क वितरण

### जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने किया अवलोकन

मूक पत्रिका



**सक्ती** :-सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के समीप स्थित जेठा ग्राउंड सक्ती में जिला स्तरीय राज्य स्थापना दिवस समारोह का गरिमामय ढंग से भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्योत्सव कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न योजनाओ पर आधारित विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। जिसके तहत जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रपात सिंह, कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ वासु जैन सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमनागरिकों ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से महतारी वंदन योजना, छत्तीसगढ़ में सड़कों का विकास, रेलवे का विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सेवा सेतु, रामलला योजना, शक्तिपीठ परियोजना एवं कृषक उन्नति योजना सहित शासन की अन्य विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित जनमन पुस्तिका का निःशुल्क वितरण भी किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से आमनागरिक छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों से अवगत हुए।

# चांपा में ABVP की भव्य शोभायात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा का दिया गया प्रशिक्षण

## 837 से अधिक छात्राओं की मौजूदगी में तेजस्विनी सम्मेलन संपन्न

मूक पत्रिका






**चांपा।** अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला जांजगीर-चांपा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तेजस्विनी युवती सम्मेलन उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में 837 से अधिक युवतियों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण तूफानी मौसम और मूसलाधार बारिश के बीच निकली भव्य शोभायात्रा रही। बारिश के बावजूद युवतियों का उत्साह कम नहीं हुआ। भारत माता की जय और युवाशक्ति के उद्घोष से चांपा शहर गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सत्यलता मिरी, परिषद वक्ता राष्ट्रीय कला मंच की प्रदेश संयोजिका रिद्धिमा वर्मा, स्वागत समिति अध्यक्ष एवं पर्वतारोही अमिता श्रीवास तथा विशिष्ट अतिथि अनुराधा शुक्ला उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि सत्यलता मिरी ने कहा कि आज की युवतियां केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खेल, विज्ञान, रक्षा, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आवश्यकता है कि उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें। विद्यार्थी परिषद ऐसे आयोजनों के माध्यम से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सराहनीय कार्य कर रही है। स्वागत समिति अध्यक्ष अमिता श्रीवास ने युवतियों में आत्मविश्वास और राष्ट्रभावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ सबसे पहले राष्ट्र को रखना है। उन्होंने युवतियों को तेजस्विनी बताते हुए ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता बताई। परिषद वक्ता रिद्धिमा वर्मा ने विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मिशन साहसी अभियान के माध्यम से हजारों छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं ऋतुमति अभियान के जरिए पिछड़ी बस्तियों और वनवासी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है।सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य विमर्श और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। सुप्रसिद्ध कथक नर्तक एवं प्रशिक्षक सुभाष यादव के निर्देशन में नूपुर नृत्य संस्था की बालिकाओं ने कृष्ण विरह की वेदना को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया। वहीं शासकीय महाविद्यालय उमरेली की छात्राओं ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ विषय पर नाटक प्रस्तुत कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला छात्रा प्रमुख अनामिका सिंह एवं नगर सह मंत्री अनामिका द्विवेदी उपस्थित रहीं। मंच संचालन अन्नू श्रीवास ने किया तथा आभार प्रदर्शन नगर मंत्री वेणुनारायण देवांगन ने किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में चांपा पीजी कॉलेज अध्यक्ष अंशिका सोनी, मंत्री सपना धीवर, उपाध्यक्ष बिंदिया देवांगन सहित निशु कटकवार, ऋतु कुशवाहा, अनुराधा द्विवेदी, हेमपुष्पा, हंसराज एवं विभिन्न इकाइयों की छात्रा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

# सतनामी समाज और साहू समाज के लोगों से मिलीं डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे, सामाजिक जनों से की मुलाकात

### रिसाली निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की दावेदार डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे की सामाजिक बैठकों का दौर जारी, विभिन्न समाजों के लोगों से की चर्चा

मूक पत्रिका



**रिसाली।** नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस की प्रमुख दावेदारों में शामिल डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे ने विगत दिनों क्षेत्र के सतनामी समाज एवं साहू समाज के सामाजिक जनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से संवाद कर अपना पक्ष रखा और आगामी नगर निगम चुनाव में समर्थन का आव्हान किया। डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे की इन मुलाकातों को चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं सामाजिक संपर्क के माध्यम से वे अपनी दावेदारी को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं।

### सतनामी समाज में विशेष पहचान, महिलाओं के बीच भी चर्चा

डॉ. रामेश्वरी वासु बंजारे को सतनामी समाज से जुड़ी महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके समर्थक उन्हें समाज की लाडली बताते हुए समाज के लोगों का समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं। महिलाओं के बीच भी उनकी दावेदारी को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल कांग्रेस में महापौर पद की दावेदारी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में सामाजिक मुलाकातों और जनसंपर्क के जरिए दावेदार अपनी सक्रियता प्रदर्शित कर रहे हैं।

# भोपालपट्टनम में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, राजस्व कार्य प्रभावित

### चार सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील के पटवारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान।

मूक पत्रिका




**बीजापुर/भोपालपट्टनम/आशीष पदमवार।** छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर भोपालपट्टनम तहसील के पटवारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटवारियों की हड़ताल के चलते तहसील क्षेत्र में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।हड़ताल पर बैठे पटवारियों की प्रमुख मांगों में पीवी ऐप में किए जा रहे कार्यों का बहिष्कार, दमनकारी निलंबन एवं स्थानांतरण की कार्रवाई को बिना शर्त वापस लेना, वेतन विसंगति दूर करना तथा राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर विभागीय पदोन्नति करना शामिल है।पटवारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। इसी के विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया है। पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी चारों मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनका निराकरण नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं, पटवारियों के आंदोलन से राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ रहा है।

## तेलंगाना-आंध्रप्रदेश-महाराष्ट्र से पहुंचे अंतरराज्यीय जुआरी पकड़ाए, कैश, मोबाइल और कारें जब्त

# मुर्गा लड़ाई की आड़ में लाखों का जुआ! पुलिस ने दोनों तरफसे रास्ता घेरकर मारी दबिश

मूक पत्रिका



**बीजापुर/आशीष पदमवार।** जिले में मुर्गा लड़ाई की आड़ में चल रहे लाखों रुपए के जुए पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपालपट्टनम ब्लॉक के रायगुड़ा गांव में जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ दबिश दी। भागने का रास्ता बंद करने के लिए एक ओर छह चक्का हाइवा और दूसरी ओर पिकअप वाहन खड़ा कर सड़क ब्लॉक कर दी गई। दोनों तरफ से घेराबंदी के बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद अंतरराज्यीय जुआरियों को पकड़ लिया।बताया जा रहा है कि रायगुड़ा में मुर्गा लड़ाई की आड़ में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा था। यहां तेलंगाना और आंध्रप्रदेश से भी लोग दांव लगाने पहुंच रहे थे। जुए में लाखों रुपए का लेनदेन होने की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की योजना बनाई।

### दोनों तरफसे रास्ता बंद कर की घेराबंदी

पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद भागने के संभावित रास्तों को बंद करने की रणनीति अपनाई। एक तरफ छह चक्का हाइवा खड़ा किया गया, जबकि दूसरी तरफ पिकअप वाहन लगाकर रास्ता रोक दिया गया। इस तरह दोनों ओर से घेराबंदी कर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। अचानक हुई कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला।

### 20 से 25 लाख रुपए कैश मिलने की जानकारी

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकदी, मोबाइल और कारें जब्त की हैं। सूत्रों के अनुसार, बरामद नकदी करीब 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि, जब्त रकम का अंतिम आंकड़ा, मोबाइल और वाहनों की संख्या तथा पकड़े गए लोगों की कुल संख्या को लेकर पुलिस का विस्तृत आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।

### एसपी बोले- मुखबिर की सूचना पर बनाई थी टीम

एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान कैश बरामद हुआ है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।




स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।